







जॉन केनेथ गैलब्रेथ

---

# आर्थिक विकास का सापेक्ष चित्रण

•

अनुवादक,  
हरिप्रताप सिंह

1963

शुभाराम एण्ड संस, दिल्ली-6

# AARTHIK VIKAS KA SAPEKSH CHITRAN

(Hindi Version of *Economic Development in Perspective*  
by

John Kenneth Galbraith

Translated by

Hari Prasad Singh

Rs. 2 00

© COPYRIGHT 1962 BY JOHN KENNETH GALBRAITH

प्रकाशक

रामलाल पुरी, संचालक

भारमाराम एण्ड सन

काश्मीरी गेट, दिल्ली-6

शाखाएँ

हीरा रास्ता, नई दिल्ली

मार्ग हीरा गेट, जालन्धर

चौड़ा रास्ता, जयपुर

बेगमपुल रोड, मेरठ

विश्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डीगढ़

महानगर, लखनऊ 6

प्रथम संस्करण : 1963

मूल्य : दो रुपए

मुद्रक

९५

देख

## प्रस्तावना

प्रस्तुत पुस्तक उन पाँच भाषणों का परिणाम है, जो मैंने भारत की पाँच प्रधान शिक्षा-संस्थाओं—मद्रास विश्वविद्यालय, बलरत्ता विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय तथा नई दिल्ली स्थित इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (सार्वजनिक प्रशासन शिक्षा संस्था) में सन् 1961 की ग्रीष्म धीरे शरद ऋतु में दिये थे। हाल के कुछ वर्षों में धार्मिक विवादों से सम्बन्धित साहित्य बड़ा विस्तृत एवं व्यापक हो गया है तथा उसकी भाषा बड़ी जटिल। ऐसी सूरत में इन बातों का खतरा हमेशा ही घना रहता है कि मुख्य बातों की उपेक्षा हो जाय। अधिकतर विवरणों में सम्बन्धित वादविवाद के उल्लाह में हम समस्या के केवल एक भग की ही पूरी समस्या मान लेने की टननी कर बैठते हैं। जैसा कि पुस्तक का नाम ही बतलाता है, इन भाषणों में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि विवाद कायें इस दृष्टि से प्रस्तुत किया जाय कि उसके महत्वपूर्ण तथा अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण सभी पहलू स्पष्ट रूप में सामने आ जायें। यह कहना बड़ाबिन् अधिक सही होगा कि पाँच

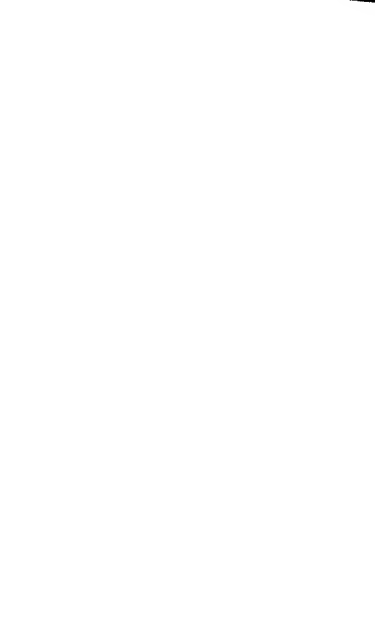
पणों में से चार का यही उद्देश्य था; पाँचवां कुछ विशिष्ट प्रकार का क्योंकि उसका सम्बन्ध इस महत्वपूर्ण समस्या से है कि औद्योगिक वित्त प्रमुख साधन, अर्थात् कम्पनी या निगम, का उपयोग किस प्रकार किया प ।

इन भाषणों में जब न केवल भारत अपितु विदेशों में भी लोगो ने कुछ त्वस्पी दिखलायी, तो मैं उन्हें पुनः इस रूप में प्रस्तुत करने के लिये ता किसी कठिनाई के ही तैयार हो गया । मुझे आशा है कि ये भाषण । समस्या को समझने में थोड़ा सहायक होंगे, जो निश्चय ही मात्र की अधिक महत्वपूर्ण एवं मानव-हित की समस्या है तथा जिसे हल करने लोग लगे हुए हैं । मैं यह नहीं कह सकता कि पुस्तक में लिखी हुई सभी जों से सब लोग सहमत होंगे । यह तो कुछ सन्तोष की बात होगी कि की असम्मति मुझमें है । सप्टेन के इस युग में कुछ ऐसी बातें होती जो व्यक्तियों की ही क्षमता एवं अधिकारक्षेत्र तक सीमित रहती । प्रस्तुत पुस्तक में जिस प्रकार की चर्चा है, वह इस बात का एक ।ाहरण है ।

## क्रम

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 1. आर्थिक विकास का सापेक्ष चित्रण | 1  |
| 2. विकारोन्मुख तथा विकसित         | 18 |
| 3. विकास नियोजन का सिद्धान्त      | 31 |
| 4 शिक्षा एवं आर्थिक विकास         | 48 |
| 5 उत्पादन का माध्यम               | 62 |





## आर्थिक विकास का सापेक्ष चित्रण

द्वितीय महायुद्ध के बाद में, ससार भर के सभी शिक्षित समाज में आर्थिक विकास के सम्बन्ध में अत्यन्त जोरदार चर्चा, वाद-विवाद आदि हुए हैं। यद्यपि तुलना करते समय हमें हमेशा ही सावधान रहना चाहिए, प्रवृत्ति में इस वाद-विवाद की तुलना उस विवाद से की जा सकती है जो स्मिथ द्वारा सन् 1776 ई० में 'राष्ट्रो की समृद्धि का स्वरूप तथा उसके कारणों' के सम्बन्ध में की गई जाँच रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात् प्रारम्भ हो गया था, तथा जिसमें अगले साठ या सत्तर वर्षों में बेन्थम, माल्थूज, जॉन स्टुअर्ट तथा कुछ अन्य लोगो ने उत्प्रेष्य योगदान किये थे। आज भी वैसा ही व्यवसर है। आज भी, उस समय की भाँति, विभिन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रीय विकास के प्रारम्भिक अवस्थानों पर हैं। एशिया तथा अफ्रीका के नवोद्भूत देश ठीक उसी प्रकार उन प्रतिस्पर्धियों को समझने के प्रयत्न में हैं, जिन पर प्रगति निर्भर होती है।

... अठारहवीं शताब्दी

... में पश्चिमी

... वर्षों में

आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक विकसित देशों के विद्वान् इन वाद-विवादों में गम्भीरता से हो गये हैं तथा कभी-कभी उन्होंने इनका गेनूय भी किया है। गत कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में विकास के अर्थ-सिद्धान्त में गहरी दिलचस्पी दिखाई गई है, इस पर अमरीकी जनता गर्व कर सकती है।

नये राज्यों तथा पुराने राज्यों दोनों में ही यह मान लिया गया है कि आर्थिक विकास एक अनिवार्य वस्तु है। वस्तुतः हाल के वाद-विवादों की यही बात पहले के वाद-विवादों की तुलना में एक विशेष बात हुई है। कम-से-कम मार्क्स के समय तक आर्थिक प्रगति की समस्या की छानबीन एक प्रकार की दार्शनिक विरक्ति के साथ हुई थी। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् से उसे अत्यन्त गम्भीर एवं आवश्यक मान लिया गया है। उन्नीसवीं शताब्दी का वाद-विवाद एक ऐसी दुनिया में हुआ था, जो उस समय जो-कुछ भी हो रहा था, उसी पर एक प्रकार से गर्व का अनुभव कर रही थी। परन्तु बीसवीं शताब्दी का वाद-विवाद एक ऐसी दुनिया में हो रहा है, जो यह महसूस करती है कि बहुत-कुछ और होना चाहिए, और वह भी बहुत शीघ्र।

विकास के सम्बन्ध में हुआ हाल का वाद-विवाद पहले के वाद-विवाद से इस अर्थ में और भी भिन्न है कि वह बहुत ही जटिल तथा तथ्यात्मक हो गया है। अब हमारे सामने प्रगति के नमूने हैं—आर्थिक प्रगति की प्रक्रिया के रूप से सम्बन्धित उप-कल्पनाएँ हैं—जिनमें कुछ तो गणित की पेचीदगियों से पूरी हैं तथा थोड़ी-सी ऐसी भी हैं, जो बिल्कुल ही समझ

पूँजी उत्पादन के अनुपातों तथा सीमान्त पूँजी-उत्पादन के अनुपातों का हिसाब अब बहुत-कुछ पाँच, सात और दस-वर्षीय योजनाओं तथा ऐसी ही भागों की भी योजनाओं के लिए सामूहिक उत्पादन के आधार पर किया जाता है। अपेक्षाकृत कम विकसित देशों में बाहर से विभिन्न प्रतिनिधि-मण्डल आते हैं, और वे अपने पूर्वनिर्दिष्ट कार्यक्रमों तक ही सीमित रहकर तथा नई मूचनाएँ एकत्र कर या पूर्वविदित बातों का ही प्रसन्नतापूर्वक पुन. अनुसंधान कर वापस चले जाते हैं और इस प्रकार एक-दूसरे से मिलना बचा जाते हैं। अब पिछड़ेपन के सम्बन्ध में एक समाज-विज्ञान तथा एक काफी बड़ा मानव-विज्ञान भी है। कहा जाता है कि सात वर्षों की अवस्था में ही मिल ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं का पण्डित बन गया था। यदि वह आज, अपनी मृत्यु के लगभग नब्बे वर्ष बाद, पुन. जन्म लेता, तो यह देखकर कि जिन विषयों पर उसने अपने समय में लिखा था, वे अब कितने जटिल हो गए हैं, कदाचित् वह प्लेटो (अफलातून) तथा जेनोफोन के साथ ही बने रहने का निर्णय करता।

परन्तु जटिलता की पूर्णता मान लेना या तथ्यात्मक विश्लेषण को बुद्धिमानी मान लेना गलती होगी। इस आधुनिक वाद-विवाद में कुछ गम्भीर त्रुटियाँ हैं। और पहले के वाद-विवाद से मुक्तता करने पर ये त्रुटियाँ स्पष्ट हो जाती हैं।

. 2 .

यह हमारे लिए गर्व की बात है कि विकास सम्बन्धी हाल का वाद-विवाद वैज्ञानिक ढंग पर हुआ है, जिसके अन्तर्गत पारि-

आर्थिक इन्हीं एक कारणों को एक ओर देखना चाहते हैं। दूसरी ओर हमें यह ध्यान रखना है कि मनुष्य के विकास के लिये वह कार्य करने वाले विद्वान् विद्वान् के साथ ही एक-दूसरे के साथ विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं, आवाज-गवाह करने वह एक-दूसरे को अपनी सुधार बताते हैं, तथा आर्थिक विद्वान् सामाजिक शांति में अन्तर्गत मान जोरकर मनुष्य के मान-भयानक को खोले कर सकता है। पहले का आर्थिक विद्वान् आर्थिकता का कम निश्चयवादी बनने अधिक विज्ञान देने पर था। विज्ञान, आर्थिक, अर्थमय तथा आर्थिक पद्धतियों के निर्माण में, उन्होंने प्रदर्शित के लिए आर्थिक मन्त्री वार्ता को चिन्ता की। अर्थमय प्रशासन के विज्ञान, वैज्ञानिक शांति के लिए अर्थमय प्रदर्शन करने वाली बात, जनसाधारण को जागरूकता का योगदान, विज्ञानवादी को साधारण-निर्माण, प्रविष्टि-योगिता तथा एक-अधिकार का प्रभाव, सामाजिक वर्गों के पारस्परिक सम्बन्ध, इन बातों के कारण कि कुछ लोग, विशेषकर अर्थमय लोग, क्यों अधिक परिश्रम करते हैं तथा कुछ अन्य लोग, विशेषकर आर्थिक लोग, क्यों कम परिश्रम करते हैं, ये सभी बातें उनकी बहुप्रयोजन वाली पणती के लिए अर्थमय के रूप में थीं। सच तो यह है कि उन्होंने जिस बात का भी आर्थिक प्रगति से सम्बन्ध सम्झा, उसी पर विचार किया। यह निर्णय करते समय कि किस बात पर विचार किया जाय, वे केवल दो ही बातें सोचते थे। आर्थिक प्रगति के लिए क्या आवश्यक है, या इसके विपरीत किस कारण से प्रगति अवरुद्ध हो जाती है—उस स्थायी, प्रचल स्थिति पर पहुँच जाती है, जिसके कारण

चटुत चर्चा हो चुकी है।

उन्नीसवीं शताब्दी का वाद-विवाद अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों द्वारा ही हुआ था। वह इस प्रकार का था ही कि कुछ ऐसे लोगों तक ही सीमित रहा, जो बड़ी-बड़ी समस्याओं को समझ सकते थे तथा उन्हें एक सूत्र में बाँध सकते थे। इस प्रकार केवल महान् व्यक्ति ही उसमें भाग ले सकते थे—हमने बहुधा ही सुन रखा है कि प्रत्येक पीढ़ी केवल एक ही दार्शनिक उत्पन्न करती है। आजकल हममें से जो बोलने आदि का प्रयत्न करते हैं, उनके सीमाय से आधुनिक वाद-विवाद अपेक्षाकृत अधिक लोकतान्त्रिक रहा है। ऐसा इसलिए है कि यह समस्या के केवल कुछ पहलुओं तक ही सीमित रहा है, न कि समूची समस्या के विषय में। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, जो समाज के प्रति एक सर्वव्यापी उपयोगी दृष्टिकोण रखते हों। बहुत-से लोग अल्प-मात्रा में ही ज्ञान का योगदान कर सकते हैं। किसी दार्शनिक अथवा धार्मिक विचार, तथा आर्थिक परिवर्तन में क्या सम्बन्ध होता है, इसे स्पष्टतया दर्शना कदाचित् आसान नहीं है। परन्तु प्रगती पंचवर्षीय योजना में मशीन-पुर्जों को लेकर प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में लगभग प्रत्येक व्यक्ति कोई-न-कोई उपयोगी सुझाव प्रदान कर सकता है।

मेरे विचार में आर्थिक विकास-सम्बन्धी आधुनिक वाद-विवाद की कमजोरी और खतरा इसी बात में है। हम उत्साह-पूर्वक और बड़ी क्षमता से समस्या के खंडों के सम्बन्ध में विचार करते आए हैं; परन्तु हमने शायद ही कभी यह सोचा हो कि क्या इन खण्डों के अलग-अलग हल से पूरी समस्या का स्याओ

रूप से हल हो जाता है। हमने उन बातों पर तो ध्यान दिया है जो आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, परन्तु यह जानने का हमने बहुत कम प्रयत्न किया है कि क्या उनका उपयोग ऐसे सन्दर्भ में हो रहा है, जो विकास के अनुकूल हो। इसके परिणाम-स्वरूप कदाचित् ऐसे कार्य करने में अपना काफी समय और प्रयत्न बरबाद किया है, जो स्वयं में तो ठीक थे परन्तु जो प्रगति में अल्पमात्र या बिल्कुल ही नहीं सहायक हुए, क्योंकि वे एक ऐसे वातावरण में किए गए थे जो प्रगति के अनुकूल नहीं था। इस वातावरण की भली भाँति जाँच नहीं की गई और जैसे-तैसे यह मान लिया गया कि वह विकास के अनुकूल है।

### . 3 .

अब मैं और स्पष्ट होना चाहता हूँ। द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बातों पर सर्वांगीण रूप से विचार करने के अभाव में, जैसा कि वह एक शताब्दी पहले हुआ था, हमने दो बातें मान रखी हैं। वे निम्न हैं :

(1) संसार विकसित तथा अर्द्धविकसित देशों के दो स्पष्ट गुटों में विभाजित है। विकसित देशों में आर्थिक प्रगति लगभग स्वचालित है—या कम-से-कम यह सम्बन्धित देश की प्रगति के परे नहीं है, वरन् वह एक मुनियोजित आर्थिक नीति का अनुसरण करता है। किसी भी अर्द्धविकसित देश में विकास सम्भव है। उसे आवश्यकता है केवल उन साधनों की, जो उसे अब तक नहीं प्राप्त हो सके हैं।

(2) ये अप्राप्त साधन, जिनको लेकर लगभग सभी एकमत हैं, हैं आधुनिक शिल्प-ज्ञान पूंजी, विशेष प्रकार से प्रशिक्षित कुछ लोग तथा पूंजी का इन प्रशिक्षित लोगों का और शिल्प-ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक ठोस योजना। यदि वे प्रदान कर दिए जाएं तो प्रगति अवश्यम्भावी है।

प्राथमिक विकास के लिए आदर्श नुस्खा इसी निदान के आधार पर तैयार होता है। शिल्प-ज्ञान सम्बन्धी सहायता विदेशों से प्राप्त की जाती है। घरेलू बचत में तथा घरेलू एवं विदेशी दोनों स्रोतों से पूंजी में वृद्धि करने के लिए उपाय किए जाते हैं। प्रशिक्षित होने के लिए कुछ लोग विदेशों में भेजे जाते हैं। एक पंचवर्षीय या सातवर्षीय या दसवर्षीय योजना तैयार की जाती है।

यह कार्य निश्चय ही निर्दोष सिद्ध होगा, बशर्ते विकास समस्या का निदान निर्दोष हो। यदि यह निदान ही दोषपूर्ण है, तो हमारे बहुत-से प्रयत्न निरर्थक एवं व्यर्थ सिद्ध होंगे। मुझे यह कहते बड़ा खेद होता है कि निदान बड़ा दोषपूर्ण है और उसमें भारी सुधार की आवश्यकता है। यह बात कि यह निदान अधिकांश अन्य देशों की तुलना में भारत के लिए लगभग उप-युक्त है, भारत में भी केवल सीमित मात्रा में ही सन्तोष प्रदान कर सकती है, क्योंकि गरीबी और दरिद्रता पर विजय प्राप्त करना एक ऐसा कार्य है जो सारी मानव जाति के लिए चिन्ता का विषय है। आइये अब हम कुछ व्यावहारिक मामलों के सन्दर्भ में इस निदान पर विचार करें।



. 4 .

इसने ऊपर कहा है कि अभाव की यस्तुएँ पूँजी तथा शिल्प-ज्ञान है। परन्तु बहुत-से नवोदित अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय सरकार धन भी प्रारम्भिक अवस्थानों पर है, तथा लेटिन अमेरिका (दक्षिणी अमेरिका) के अनेक भागों में वह कार्यक्षमता के निम्न-तम स्तर पर भी कभी नहीं पहुँच सकी है। इन परिस्थितियों में पूँजी लगाने में, चाहे वह सार्वजनिक पूँजी हो या निजी, दोष-पूर्ण सार्वजनिक प्रशासन जन्य-जोखिमों, अनिश्चितताओं तथा अनियमितताओं का भय बना रहता है। यह सोचना व्यर्थ है कि बिना किसी अच्छी सरकार के अच्छी विकास योजनाएँ तैयार या कार्यान्वित की जा सकती हैं। और, जब प्रशासन ढीला या दोष-पूर्ण हो, तो न तो शिल्प-ज्ञान सम्बन्धी सहायता और न प्रशिक्षित शिल्पी ही कुछ कर सकते हैं, और वे बहुत आवश्यक भी नहीं होते। सर्वश्रेष्ठ कृषि-वैज्ञानिक को भी यदि किसी निर्जीव मंत्रालय का सलाहकार बनना हो, तो वह क्या कर सकता है? कर-सम्बन्धी अच्छा-से-अच्छा अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, यदि सम्बन्धित मंत्री कर वसूल करने में विश्वास नहीं करता, बैसा करना भी नहीं चाहता या अपने मित्रों के प्रति आवश्यकता से अधिक सहृदयता का भाव रखता है। ऐसी सूरत में पहला काम पूँजी या टेकनीशियनों का प्राप्त करना नहीं है, अपितु सार्वजनिक प्रशासन के सभी अवयवों को सुदृढ़ बनाना है।

गत शताब्दी में आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के लिए सभी आवश्यक बातों में जितना महत्वपूर्ण स्थान सार्वजनिक शिक्षा तथा लोक जागरण को दिया गया था, उतना अन्य किसी

को नहीं। आज के नवोदित राष्ट्रों में, या उन पुराने राष्ट्रों में, जहाँ लोक शिक्षा विकसित रूप में नहीं हो रही है, स्कूली पुस्तकों को मशीन के धोखारे की तुलना में बरीयता दी जानी चाहिए। लोकशिक्षा कुछ थोड़े से लोगों की नहीं, अपितु भारी संख्या में लोगों की प्रतिभा प्रस्फुटित करती है। और वह शिल्प-ज्ञान का द्वार खोल देती है। पढ़े-लिखे लोग ही यह समझेंगे कि मशीनों की अब आवश्यकता है। परन्तु यह कैसे कहा जा सकता है कि मशीनें यह समझेंगी कि पढ़े-लिखे लोगों की आवश्यकता है। इस प्रकार, कम-से-कम कुछ परिस्थितियों में लोकशिक्षा को बाँधो, कारखानों तथा पूँजी बढ़ाने के अन्य साज-सामानों की तुलना में बरीयता मिलेगी।

अतः में, बहुत-से देशों में सम्पूर्ण पद्धति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर सामाजिक व्यवस्था की घुटियों पर ही दृष्टि पड़ेगी—उन व्यवस्थाओं पर जिनके अन्तर्गत धन और राज-नीतिक मत्ता जनसमुदाय के एक छोटे-से अल्प-सङ्ख्यक वर्ग के ही एकाधिकार है और परिणामतः जनसाधारण उन्नति के सभी उपकरणों से दूर ही रखा जाता है। अच्छा-से-अच्छा कृषि-मुधार विशेषज्ञ गेहूँ के एक दाने के स्थान पर दो दाने पैदा करने का फायदा नहीं समझ सकता, यदि कृषक यह भली भाँति जानता है कि ये दोनों दाने अनिवार्यतः उसके जमींदार के पास ही पहुँच जायेंगे। कृषि-उत्पादन में पूँजी लगाने के अच्छे-से-अच्छे रूप या कृषि-विस्तार की अच्छी-से-अच्छी शैलियाँ व्यर्थ हैं, यदि किसान युगों के अपने अनुभव से यह जानता है कि उससे प्राप्त होनेवाले लाभ उसे नहीं मिलेंगे।

संशोध में, समस्या पर एक गरसरी निगाह डालने पर भी, अच्छी और दक्ष सरकार, शिक्षा तथा सामाजिक न्याय मामिक रूप से महत्वपूर्ण योग पड़ते हैं। अनेक देशों में, प्रगति में बाधक बातों को जान करने पर पता चलता है कि इन्हीं बातों की कमी ही सामिक रूप से महत्वपूर्ण है। इससे यह परिणाम निकलता है कि जब तक ये बाधाएँ दूर नहीं कर दी जाती, पूँजी लगाने तथा शिल्प-ज्ञान की सहायता से कोई लाभ नहीं होगा। कागज पर भले ही योजनाएँ बड़ी बन जाएँ, उनसे परिणाम सूदम ही निकलेंगे।

. 6 .

मैंने ऊपर कहा है कि विकसित न होने के कारण का यह निदान, जिसमें पूँजी, शिल्प-ज्ञान की सहायता तथा नियोजन पर अधिक बल दिया जाता है, भारत जैसे देश के मामले में कोई बहुत अनुपयुक्त नहीं है। भारत में एक अच्छी और दक्ष सरकार है, शिक्षित लोग भी काफी संख्या में हैं; प्रशासकीय तथा उपक्रमी प्रतिभा के लोग भी यहाँ काफी संख्या में हैं, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक प्रगति प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित रूप से निर्दिष्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ व्यय करने की प्रवृत्ति अधिक है तथा बचाने की कम, और पूँजी उपलब्ध करने की समस्या उस अंश के लिए विशेष रूप से गंभीर है, जिसे विदेशों से प्राप्त करना है। इन परिस्थितियों में पूँजी लगाने के कार्य में वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर स्वभावतः ध्यान केन्द्रित हो गया है।

विकास समस्या को गलत समझने का यहाँ एक महत्वपूर्ण

कारण है। चीन को छोड़कर, अर्द्धविकसित देशों में भारत का क्षेत्र सबसे बड़ा तथा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। उसके विकास के प्रश्न ने जितना ध्यान आकर्षित किया है, उतना अन्य किसी देश के नहीं। इसका एक कारण तो यह है कि उसके पास अत्यंत कुशल आयोजक तथा अत्यन्त अोजस्वी पत्रकार एवं प्रोफेसर हैं। भुटियो के बावजूद, भारत के पास सर्वश्रेष्ठ आँकड़े भी हैं, और जैसा कि सभी अर्थशास्त्री जानते हैं, किसी ऐसे देश के विकास के सम्बन्ध में योजना आदि तैयार करना बड़ा कठिन है, जिसके सम्बन्ध में मोटे तौर पर राष्ट्रीय उत्पादन के एक काल्पनिक आँकड़े भी न उपलब्ध हों। इसका परिणाम यह हुआ है कि सारा संसार भारत के अनुभव को ही, या यह कहना अधिक सही है, कि भारत तथा पाकिस्तान के अनुभव को ही, विकास की संज्ञा देने लगा है, और जिस हद तक वास्तव में ऐसा समझा जाने लगा है, उससे बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं। चूंकि इन देशों में पूँजी तथा प्रशिक्षित टेक्नीशियनों की कमी ही विकास में बाधक है, अन्य देशों में भी ये ही बातें बाधक समझी जाने लगी हैं। चूंकि भारत तथा पाकिस्तान में कुशल नियोजन संभव है, ऐसा मान लिया जाता है कि वह सभी जगह संभव है।

पूँजी तथा प्राविधिक शिल्प-ज्ञान एवं शिल्पियों पर जो आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है, उसके लिये कुछ अंश में संयुक्त राज्य अमेरिका भी जिम्मेदार है। राष्ट्र के रूप में हमारे हृदयों में ऐसे तथा उसके उपयोगों के लिए एक यथोचित आदर है। और अमेरिका में कोई आर्थिक सफलता सरकार की बदलती हुई इच्छा पर नहीं आधारित होती, उचित सामाजिक



चाहिए कि आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है—ऐसी प्रक्रिया जिसका विस्तार अफ्रीका के नये राष्ट्रों से लेकर पाश्चात्य देशों के विशाल आर्थिक और सामाजिक ढाँचे तक, परन्तु उनके आदिम जातीय ढाँचे से तनिक भिन्न रूप में फैला हुआ है। इस अनवरत प्रक्रिया के प्रत्येक अवस्थान पर वहाँ में आगे बढ़ने के लिए एक उप-युक्त नीति होती है। जो नीति किसी एक अवस्थान के लिए सही होती है, वह किसी दूसरे अवस्थान के लिए गलत होती है।

प्रारम्भिक अवस्थानों में निश्चय ही उगमें मार्बंजनिक प्रशासन के विभिन्न अवयवों का निर्माण करना तथा कुछ निश्चित अल्पमर्यादों की व्यवस्था करना आवश्यक होता है, ऐसे लोगों का एक ग्रुप समूह, जो मार्बंजनिक प्रशासन की पद्धति का तथा उसमें सम्बन्धित अन्य बातों का निर्माण कर सकें। इसके बाद लोक जागरण का काम आता है। यह जागरण जन-साधारण की आर्थिक क्रियाकलाप में भाग लेने के योग्य बना देता है। और यह लोगों के मस्तिष्कों की नये तराई तथा नई नीतियों के ऐसा अनुकूल बना देता है, जैसा वे अन्य किसी तराई में नहीं बन सकते। सांस्कृतिक पहलू के अनिश्चित, लोक मिथ्या एक बड़ी अच्छी तथा उपयोगी वस्तु है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि यह लोक प्रेरणा का प्रमुख स्रोत भी है। ऐसा होने के

1. यद्यपि प्रोवेसर रोस्टोव के तर्क अनिवार्य विचारणीय होते हैं, उनका अनुपम योगदान यह हुआ है कि उन्होंने विकास की समस्या पर विचार आदि की बड़ अद्भुत दृष्टि दे रखी और सोच दिया है। (दोस्त बेमिद्व द्वारा सन् 1963 में प्रकाशित 'दो स्ट्रेट्स टू द डेवेलपिंग सोस'।)

माता-पिता उत्पन्न करने पर नहीं आधारित होती, निश्चित कर्म-धारी ईद देने पर नहीं आधारित होती, क्योंकि ये वस्तुएँ तो उत्पन्न नहीं हैं। और ऐसा मान लिया जाता है कि वे हैं। यह गलतनी। पुत्रों प्राप्ति करने तथा दत्तों-निर्धारों, धनानिर्धारों और दत्तों-निर्धारों की भरती करने पर आधारित होती है। तदर्थ में, गंगा में दत्त एतियायी उप-महाद्वीप के अनुभव के आधार पर एक मध्यस्थानों निर्धारण निकाल लिया है, और हमने अपने ही अनुभव पर ऐसा व्यापक नियम बना लिया है। जो लोग इन मामलों में महयोग की गराहना करने हैं, उन्हें यह मोचना चाहिए कि यह प्राथमिक शिक्षा के विद्यार्थियों को गुमराह भी कर सकता है।

. 0 .

इससे क्या शिक्षा मिलती है ? यह बात नहीं है कि पूँजी या प्राथमिक सहायता या शिल्प-प्रशिक्षण महत्वपूर्ण नहीं है या नियोजन समय की बरबादी है। भारत, जहाँ ये बातें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, इसके खडन में उवलंत उदाहरण है। शिक्षा यह मिलती है कि अविकास के कारणों का अब केवल एक निदान नहीं हो सकता। इसके विपरीत, अमुक देश के लिए अमुक प्रकार का उसी के उपयुक्त निदान होना चाहिए। और ऐसे बहुत थोड़े से ही देश होंगे, जिनमें पिछड़ेपन के कारण या प्रगति की आवश्यकताएँ एक ही हों।

अधिक स्पष्ट रूप में कहा जाए, तो हमें यह मान लेना

चाहिए कि धार्मिक विकास एक प्रक्रिया है—ऐसी प्रक्रिया जिसका विस्तार अफ्रीका के नये राष्ट्रों से लेकर पाश्चात्य देशों के विशाल धार्मिक और सामाजिक ढाँचे तक, परन्तु उनके आदिम जातीय ढाँचे से ननिक भिन्न रूप में फैला हुआ है। इस अनवरत प्रक्रिया के प्रत्येक अवस्थान पर वहाँ में आगे बढ़ने के लिए एक उप-युक्त नीति होनी है। जो नीति किसी एक अवस्थान के लिए सही होनी है, वह किसी दूसरे अवस्थान के लिए गलत होती है।

प्रारम्भिक अवस्थानों में निश्चय ही उसमें सार्वजनिक प्रशासन के विभिन्न अवयवों का निर्माण करना तथा कुछ शिक्षित अल्पसंख्यकों की व्यवस्था करना आवश्यक होता है, ऐसे लोगों का एक अल्प समूह, जो सार्वजनिक प्रशासन की पद्धति का तथा उसमें सम्मिश्रित अन्य बातों का निर्माण कर सकें। इसके बाद लोक जागरण का काम आता है। यह जागरण जन-साधारण को धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने के योग्य बना देता है। और वह लोगों के मस्तिष्कों को नये तरीकों तथा नई शैलियों के ऐसा अनुकूल बना देता है, जैसा वे अन्य किसी तरीके से नहीं बन सकते। सांस्कृतिक पहलू के अतिरिक्त, लोक शिक्षा एक बड़ी अच्छी तथा उपयोगी वस्तु है। कहने की आवश्यकता नहीं, कि वह भी है। ऐसा होने के

तः विवादग्रस्त होते हैं,  
बात की समस्या पर  
दिया है।

रचना-



कारण वह विकास की अभिलाषा को बलवती बना देता है।

यदि विकास को जनता के सहयोग पर आधारित होना है, तो ऐसी किसी व्यवस्था का रहना भी आवश्यक है, जिससे जनता को उसका पुरस्कार मिल सके। जब तक जन-समूह सहयोग नहीं करता, कोई सार्थक प्रगति नहीं हो सकती; और स्वभाव से ही मनुष्य ऐसा नहीं होता कि वह किसी दूसरे की मलाई के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दे। जिस प्रकार पार्श्व-लियाई आर्थिक प्रगति के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार सामाजिक न्याय भी।

इस प्रक्रिया के आगे के अवस्थानों पर बहने पर अन्य आवश्यकताएँ सामने आती हैं, और आयाती तथा प्राकृतिक साधनों के अनुसार, ये विभिन्न देशों के लिए भिन्न होंगी। पूँजी केवल उन्हीं देशों में विकास की कमीदी बन जागी है, उनके मार्ग में एक अनिवार्य बस्तु के रूप में आती है, जो इस विकास प्रक्रिया में काफी बाधा बढ़े होने है। इस बात की सम्पूर्ण पूर्ण सम्भारना है कि विकास के प्रारम्भिक अवस्थानों के देशों को प्रदान की गई पूँजी बरबाद हो जाय। विकास के काफी आगे के अवस्थान पर ही उसका निमी भी मार्ग में बृद्धिमत्तापूर्ण रूप से उपयोगी रूप से प्रयोग हो गया है।

स्पष्टता, उपलब्ध साधनों का पूर्णतः उपयोग करने की क्षमता, राष्ट्रीय लक्ष्यों की स्पष्टता—जिनकी हमें यहाँ चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं।

यदि विकास की इस प्रक्रिया को एक ऐसी पंक्ति के रूप में देखा जाय, जिसमें समार के विभिन्न देश विकास के अपने विभिन्न अवस्थानों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर स्थित दिख-साये गये हों, तो विकास की प्रक्रिया तथा तन्मध्यस्थी नीति दोनों ही बहुत स्पष्ट हो जाएँ।

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि हम विकास के लिए एक आम नुस्खे की बात नहीं कर सकते। ऐसा बोर्ड आम पार-मूला (मूल) प्रदान करने का प्रयत्न करवादी, पराजय तथा निराशा ही ला सकता है और इसी प्रकार विकास के किसी समुक्त अवस्थान पर पहुँचे हुए किसी समुक्त देश के अनुभव के आधार पर किसी अन्य अवस्थान पर पहुँचे हुए किसी अन्य देश की आवश्यकताओं के लिए बोर्ड नियम बना देना भी घातक होगा। अमेरिका के अनुभव के आधार पर भारत की आवश्यकताओं के लिए बोर्ड आम नियम निश्चित करना गलत सिद्ध होगा, और ठीक इसी प्रकार भारत के आधार पर दक्षिण के लिए बोर्ड आम नियम बनाना गलत होगा।

चाहिए। इन प्रारम्भिक अवस्थानों में विकास के समक्ष बंद घेरे की समस्याएँ भी उपस्थित हो जाती है। ऐसा कोई देश, जिसमें सार्वजनिक प्रशासन के अवयव दक्ष नहीं होते, उन्हें विकसित क्योंकर कर सकता है, क्योंकि दोषपूर्ण सरकार स्वयं-सुधारक नहीं होती, अपितु वह स्वयं को उसी रूप में बनाये रखने वाली होती है। ऐसा कोई देश, जिसमें कुछ चुने हुए शिक्षित लोग नहीं होते, उन्हें क्योंकर उत्पन्न करे, क्योंकि शिक्षा-प्रसार के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। समाज-सुधार क्योंकर किया जाय, जब वर्ग का ढाँचा ही ऐसा हो कि वह राजनैतिक सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में दे देवे, जो संभवतः उसका विरोध करें? ये बड़े ही जटिल प्रश्न हैं, यद्यपि इतने जटिल नहीं, जितने वे दीख पड़ते हैं। आखिरकार बहुत-से देश इस घेरे को तोड़कर बाहर आ गए हैं और आधुनिक युग में विकास करने की इच्छा एक प्रबल स्वतन्त्र शक्ति है, और वह उन लोगों के साथ रच-भाव भी दया नहीं दिखलाती, जो अपने निहित स्वार्थों के लिए उसके मार्ग में बाधा के रूप में आते हैं। कुछ भी हो, जिन लोगों को विकास की चिन्ता है, वे इन बाधाओं को यह मानकर नहीं दूर कर सकते कि वे तो हैं ही नहीं।

जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, ऐसे देशों में, जो ये प्रारम्भिक समस्याएँ हल कर चुके हैं, पूँजी तथा शिल्प-ज्ञान बाधा के रूप में आ जाते हैं। भारत की पूँजी की वर्तमान आवश्यकता विकास स्तर पर आधारित नहीं है। अन्य नये राष्ट्रों की तुलना के उसके उच्चतर स्तर का ही परिणाम है कि वह प्रभावी उत्पादक ढंग से प्रयोग कर सकता है।

अवस्थान पर ही, जहाँ यह मोचना पड़ता है कि अल्प मात्रा में उपलब्ध पूँजी का किम प्रकार अच्छे से अच्छा प्रयोग किया जाए, तथा जहाँ पूँजी के विभिन्न उपयोगों का एक कड़ी में जोड़ना और एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट करना आवश्यक होता है, नियोजन कार्य बड़ा जटिल हो जाता है। इससे बढ़कर और कोई गलती नहीं होगी, यदि हम यह सोचें कि जिन प्रकार की योजनाएँ भारत या पाकिस्तान में बनी हैं, उसी प्रकार की योजनाएँ विकास के सभी अवस्थानों पर पहुँचे हुए देशों के लिए भी आवश्यक हैं। प्रारम्भिक अवस्थानों पर न तो वह आवश्यक हो हैं और न समर्थ ही।

## विकासोन्मुख तथा विकसित

मैंने पिछले अध्याय में कहा है कि विकासोन्मुख देशों की तुलना एक पंक्ति में क्रमिक रूप से खड़े हुए व्यक्तियों से की जा सकती है। इन देशों की इस पंक्ति में जो देश आगे थे, उनकी स्थिति बड़ी सुविधापूर्ण थी। अग्रणी राष्ट्र—ब्रिटेन, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका—अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन, जैसी भी वे थी, उसीके आधार पर कर सकते थे। उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया, उस पर वे सन्तोष प्रकट कर सकते थे; क्योंकि किसी अन्य ने उनकी अपेक्षा अच्छा नहीं किया था। उन्नीसवीं शताब्दी में सारा ब्रिटेन अपनी उपलब्धियों पर इठला रहा था। यही बात बीसवीं शताब्दी में अमेरिका के सम्बन्ध में आज भी कही जा सकती है। इसके विपरीत, जो देश इस शृंखला में बाद की पंक्ति में थे, वे अकेले तथा दुष्प्राप्य मापदण्ड मिले, जो स्वयं स्थापित नहीं हुए थे। उन्हें प्रत्येक कदम पर अपनी तुलना करनी पड़ती है—अमेरिकी या रूसी देशों से तुलना करनी पड़ती है, अमेरिकी या रूसी से तुलना करनी पड़ती है।

एक और अनुविधापूर्ण बात है। मानव व्यापार की अत्यन्त दोषपूर्ण व्यवस्था में विकास ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, उसकी प्रगति अपेक्षाकृत आसान होती चली जाती है। ऐसा इसलिए है कि इन प्रक्रिया में प्रत्येक कदम अगले कदम को अनिवार्यतः आसान बना देता है। मार्बजनिन प्रशामन में यदि कुछ दक्ष तथा कुशल व्यक्ति न हों, तो किसी को भी विकसित करना कठिन हो जाय। परन्तु, यदि कुछ अच्छे लोग हों, जो दूसरों को भी प्रशिक्षित कर सकें तो शीघ्र ही इसका विस्तार हो सकता है। यदि कोई शिक्षक न हो तो किसी भी शिक्षा-पद्धति का आरम्भ करना कठिन हो जाय। परन्तु यदि थोड़े-से भी अच्छे शिक्षक हों तो वे दूसरों को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं और इस प्रकार यदि बहुत-से शिक्षक हो जाएँ, तो प्रशिक्षण की प्रक्रिया आसान तथा लगभग स्वचालित हो जाती है। बचत करना तथा पूँजी एकत्र करना किसी गरीब देश में, जहाँ वर्तमान आवश्यकताओं का दबाव बहुत अधिक होता है, अत्यन्त कठिन है। परन्तु किसी अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध समुदाय में बचत करना बहुत आसान है। और किसी धनाढ्य देश में तो बचत प्रचुर मात्रा में हो सकती है।

इस व्यवस्था का परिणाम यह है कि अपेक्षाकृत अधिक विकसित देश अपने से पिछड़े हुए देशों पर प्राप्त अपनी सुविधा को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कभी-कभी तो वे इन पिछड़े हुए देशों को ही उनकी धीमी प्रगति के लिए दोषी ठहराते हैं। और इन बेचारे पिछड़े हुए देशों के लिए प्रगति बहुधा ही निराशाजनक लगती है। क्या ही अच्छा होता, यदि हम सभी यह अनु-

## विकासोन्मुख तथा विकसित

मैंने पिछले अध्याय में कहा है कि विकासोन्मुख देशों की तुलना एक पंक्ति में श्रमिक रूप से रहें हुए व्यक्तियों से की जा सकती है। इन देशों की इस पंक्ति में जो देश आगे थे, उनकी स्थिति बड़ी सुविधापूर्ण थी। अग्रणी राष्ट्र—ब्रिटेन, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका—अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन, जैसी भी वे थी, उसीके आधार पर कर सकते थे। उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया, उस पर वे सन्तोष प्रकट कर सकते थे; क्योंकि किसी अन्य ने उनकी अपेक्षा अच्छा नहीं किया था। उन्नीसवीं शताब्दी में सारा ब्रिटेन अपनी उपलब्धियों पर इठला रहा था। यही बात बीसवीं शताब्दी में अमेरिका के सम्बन्ध में आज भी कही जा सकती है। इसके विपरीत, जो देश इस श्रृंखला में बाद को आए, उनके समक्ष ऊँचे तथा दुष्प्राप्य मापदण्ड मिले, जो स्वयं उनके द्वारा निर्धारित नहीं हुए थे। उन्हें प्रत्येक कदम पर अपनी उपलब्धियों की तुलना करनी पड़ती है—अमेरिकी या रूसी उत्पादन सफलताओं से तुलना करनी पड़ती है, अमेरिकी या ब्रिटिश जीवन स्तरों से तुलना करनी पड़ती है।

एक और अमुविधापूर्ण बात है। मानव व्यापार की अत्यन्त दोषपूर्ण व्यवस्था में, विकास ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, उसकी प्रगति अपेक्षाकृत आसान होती चली जाती है। ऐसा इसलिए है कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक कदम अगले कदम को अनिवार्यतः आसान बना देता है। मार्थजनिक प्रशासन में यदि कुछ दश सप्ताह कुशल व्यक्तित्व न हो, तो किसी को भी विकसित करना कठिन हो जाय। परन्तु, यदि कुछ अच्छे लोग हों, जो दूसरों को भी प्रशिक्षित कर सकें तो शीघ्र ही इसका विस्तार हो सकता है। यदि कोई शिक्षक न हो तो किसी भी शिक्षा-पद्धति का आरम्भ करना कठिन हो जाय। परन्तु यदि थोड़े-से भी अच्छे शिक्षक हों तो वे दूसरों को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं और इस प्रकार यदि बहुत-से शिक्षक हो जाएँ, तो प्रशिक्षण की प्रक्रिया आसान तथा लगभग स्वचालित हो जाती है। बचत करना तथा पूँजी एकत्र करना किसी गरीब देश में, जहाँ वर्तमान आवश्यकताओं का दबाव बहुत अधिक होता है, अत्यन्त कठिन है। परन्तु किसी अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध समुदाय में बचत करना बहुत आसान है। और किसी धनाढ्य देश में तो बचत प्रचुर मात्रा में हो सकती है।



भव कर सकते, कि अपेक्षाकृत हम अनुकूल स्थिति में रहने वाले देशों की प्रगति की चाल अनिवार्यतः इसलिए धीमी नहीं है कि उनके प्रयत्नों में कमी है । सम्भवतः इसका कारण यह है कि उनका कार्य ही अपेक्षाकृत बहुत कठिन है ।

.2.

यदि हम विश्व के देशों को विकसित तथा प्रद्वैविकसित दो स्पष्ट विभाजनों के रूप में न मानकर, उन्हें विकास-क्रम के विभिन्न सोपानों पर पहुँचे हुए मानें, तो सहायता प्रदान करने की समस्या का सहो विग्र सामने आ सकता है। क्योंकि विकास को इस दृष्टि से देखने पर हमें पता चलता है कि देशों का कोई भी समूह केवल सहायता देने के लिए ही विशिष्ट रूप से योग्य नहीं है, और न तो दूसरा समूह केवल इस स्थिति में है कि यह सर्वदा सहायता का भिखारी ही हो। सच तो यह है कि प्रत्येक देश को अपने से आगे वाले देशों से कुछ प्राप्त करना होता है। और वह अपने से पीछे वाले देशों को कुछ प्रदान करता है। सहायता की व्यवस्था एक ऐसे सहकारी प्रयत्न के रूप में प्रकट होती है (और उसे उसी रूप में देखना भी चाहिए), जिसमें सभी देश भाग ले सकते हैं।

और यद्यपि इस क्रम का पर्यवेक्षण करने पर यह पता चलता है कि दी जाने वाली सहायताओं तथा प्राप्त करने वाली गृहाय-  
ताओं में भ्रम है, मैं इसे निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि  
कम विकसित देशों का योग अनिवार्यतः कम ही है। धनःशा-  
सत अधिक विज्ञान २०० ३ ६०० तरीकों को व्यवस्था करना

सहायता का एक मुला हुआ रूप है। परन्तु भारत जैसे देश, जिस ढंग से सामान्य शिक्षा, परिवार नियोजन तथा भूमि की चकवन्दी की अपनी समस्याएँ हल कर रहे हैं, वह अनुभव इस क्रम में आने वाले देशों के लिए बड़ा ही मूल्यवान् होगा। मैं तो यहाँ तक कहने का साहस करूँगा कि इन क्षेत्रों में भारत प्रमे-रिका की अपेक्षा अच्छा शिक्षक हो सकता है। व्यावहारिक रूप में वह समस्या के बहुत निकट है।

मैं इस सिद्धान्त को स्पष्ट रूप में दुहराना चाहता हूँ। विद्युत को सहायता देने वाले तथा सहायता प्राप्त करने वाले देशों के गुटों में विभाजित करना गलत तथा मनोवैज्ञानिक रूप में गलत-नाक है। देश विकास का कार्य ऐसा है जिसमें अनेक को सहायता की आवश्यकता पड़ती है और उनकी ही मर्यादा में सहायता प्रदान कराने वाले देश भी होते हैं। अब मैं हमें इस कार्य को इसी रूप में देखना है।

### 3.

अब मैं विकासक्रम के विभिन्न अवस्थानों पर पहुँचे हुए विभिन्न देशों के बीच साधनों तथा अनुभव के सामंजस्य, सादान-प्रदान के सम्बन्ध में विशेष तौर पर कुछ कहना चाहता हूँ। यदि यह मान लिया जाए कि विभिन्न देश विकास के विभिन्न अवस्थानों पर हैं, तो हमने अधिक स्वाभाविक कहा होगा कि पिछड़े हुए देश उन देशों से सब-प्रदर्शन की अपेक्षा करें जो उनसे आगे बढ़े हुए हैं। और हमने अधिक दादनीय भी और कुछ नहीं है कि आगे बढ़े हुए देश अपने में

भय कर गाने, कि अपेक्षाकृत हम अनुकूल स्थिति में रहने वाले देशों की प्रगति को मान्य अनिवार्यतः हमारे धीमी नहीं है कि उनके प्रयत्नों में कमो है । सम्भवतः हमारा कारण यह है कि उनका कार्य हो अपेक्षाकृत बहुत कठिन है ।

## . 2 .

यदि हम विश्व के देशों को विकसित तथा अर्द्धविकसित दो स्पष्ट विभाजनों के रूप में न मानकर, उन्हें विकास-क्रम के विभिन्न गोपानों पर पहुँचे हुए मानें, तो सहायता प्रदान करने की समस्या का गही चित्र सामने आ सकता है । क्योंकि विकास को इस दृष्टि से देखने पर हमें पता चलता है कि देशों का कोई भी समूह केवल सहायता देने के लिए ही विशिष्ट रूप से योग्य नहीं है, और न तो दूसरा समूह केवल इस स्थिति में है कि वह सर्वदा सहायता का भिखारी ही हो । सच तो यह है कि प्रत्येक देश को अपने से आगे वाले देशों से कुछ प्राप्त करना होता है । और वह अपने से पीछे वाले देशों को कुछ प्रदान करता है । सहायता की व्यवस्था एक ऐसे सहकारी प्रयत्न के रूप में प्रकट होती है (और उसे उसी रूप में देखना भी चाहिए), जिसमें सभी देश भाग ले सकते हैं ।

और यद्यपि इस क्रम का पर्यवेक्षण करने पर यह पता चला है कि दी जाने वाली सहायताओं तथा प्राप्त करने वालों में अन्तर है, मैं इसे निश्चित रूप से नहीं कहूँ । कम विकसित देशों का योग अनिवार्यतः कम ही । कृत अधिक विकसित देशों के लिए पंजी की ।

भी है।

अचानक ही यह मोचना बड़ा कठिन है कि कोई कम विकसित देश पूँजी की प्रचुरता से क्षतिग्रस्त हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा है, विकास के ऊँचे अवस्थानों पर पहुँचे हुए देश कम विकसित देशों की अपेक्षा यही ग्रामांसी से पूँजी एकत्र कर लेते हैं। यह एक कारण है कि विकसित तथा कम देशों के बीच रियायती दत्तों पर—यह उन कम या शून्य व्याज की दर पर काल्पीन-ऋण का लेन-देन सामान्य तथा स्वाभाविक बात समझनी चाहिए। ऐसी किसी आर्थिक सहायता से किसीको अत्यधिक प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए, जो  $6\frac{1}{2}$  प्रतिशत व्याज की दर पर हम दण्ड के लिए दिए गए ऋण के रूप में हो। विकास के प्रारम्भिक अवस्थान का कदाचित् ही कोई देश शुद्ध वाणिज्यिक ऋण का मूल्य ग्रामांसी से अदा कर सके।

परन्तु निम्न या शून्य व्याज की दर पर दिए गए ऋणों या पूँजी के प्रत्यक्ष अनुदानों में भी अपनी बुराइयाँ हैं। किसी भी मात्रा में पूँजी के उपयोग करने की क्षमता स्वयं विकास का परिणाम है। यदि वह तभी उपलब्ध हो जाए, जब उसके उपयोग करने की अनुकूल स्थिति उपलब्ध न हुई हो, तो वह अप्रभावकारी ढंग से उपयोग में लाई जाएगी या संभवतः वह बरबाद हो कर दी जाएगी। यदि विद्युत्-शक्ति तथा परिवहन के साधन किसी प्रशिक्षित, पढ़े-लिखे तथा सामाजिक रूप से जागृत जन-समुदाय (देश) को दिए जाएँ तो निश्चित है कि वे उपयोगी सिद्ध होंगे। परन्तु यदि ये वस्तुएँ किसी ऐसे जन-समुदाय (देश) को प्रदान की जाएँ, जो अब भी अज्ञान तथा पिछड़ी हुई सामाजिक

पीछे के देशों को अनुभव तथा उचित सहायता प्रदान करें। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् से इस प्रकार के अनुभव तथा साधनों का लेन-देन एक सामान्य बात हो गई है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें मध्यम राज्य अमेरिका काफी भागे रहा है। मैं बराबर ही इस मत का रहा हूँ कि विदेश के राष्ट्रों को दिया जाने वाला यह हमारा सर्वाधिक स्मरणीय योगदान होगा।

परन्तु, विकास-क्रम के विभिन्न अवस्थानों पर पहुँचे हुए देशों के बीच लेन-देन एक ऐसा मामला है, जिसमें बहुत मोच-विचार तथा सही-गलत के पहचान की आवश्यकता है। सही और गलत दोनों ही वस्तुएँ दी और ली जा सकती हैं। दूसरों का अनुभव बुद्धिमानी से अपने लिए उपयोगी बनाया जा सकता है और फिर उससे बड़ा लाभ हो सकता है। और दूसरों की कार्यपद्धति को विवेकहीनता से अपनाया जा सकता है, जिसका परिणाम निश्चित रूप से हानिकारक हो सकता है। इन कठिनाइयों तथा खतरों के बावजूद, द्वितीय महायुद्ध के बाद विकसित होने वाले क्षेत्रों के बीच लेन-देन का अधिकांश कार्य, विशेषकर अनुभव के लेन-देन का कार्य बड़ी लापरवाही से किया गया है, मानो उसमें कोई समस्या ही नहीं है। इसको मैं और भी विवरण सहित समझाता हूँ।

विकास-क्रम में आगे बढ़े हुए किसी देश के पास तीन ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिन्हें उससे पिछड़े हुए देश भी ले सकते हैं। ये हैं—1. पूँजी, 2. शिल्प-विज्ञान, 3. संघटन। विकास-क्रम के विभिन्न अवस्थानों पर पहुँचे हुए देशों के बीच इनमें से प्रत्येक वस्तु के आदान-प्रदान से लाभ भी हो सकता है और उसमें खतरा

भी है।

अन्ततः ही यह सोचना बड़ा बहिष्कार है कि कोई कम विकसित देश पूँजी की प्रचुरता में लानिद्वेष हो जाए। और जैसा कि हमें पता है, विकास के ऊँचे अवस्थाओं पर पहुँचे हुए देश कम विकसित देशों की प्रेरणा बड़ी आसानी से पूँजी एकत्र कर सकते हैं। यह एक कारण है कि विकास तथा कम देशों के बीच विभाजनीयता पर—यह कम या दृश्य व्याज की दर पर कालीन-वृद्धि का सेतु-देन सामान्य तथा स्वाभाविक बात समझनी चाहिए। ऐसी विनी धार्मिक महायन्त्र में किमीको प्रत्यक्ष प्रभावित नहीं हो जाना चाहिए, जो ६ प्रतिशत व्याज की दर पर हम देश के लिए दिए गए ऋण के रूप में हो। विकास के प्रारम्भिक अवस्थान का कदाचित् ही कोई देश शुद्ध धार्मिक प्रणाली का मूल्य आसानी से अदा कर सके।

परन्तु निम्न या दृश्य व्याज की दर पर दिए गए ऋणों या पूँजी के प्रत्यक्ष अनुदानों में भी अपनी बुराई है। किसी भी मात्रा में पूँजी के उपयोग करने की क्षमता स्वयं विकास का परिणाम है। यदि वह तभी उपलब्ध हो जाए, जब उसके उपयोग करने की अनुकूल स्थिति उपलब्ध न हुई हो, तो वह अप्रभावकारी ढंग से उपयोग में लार्दी जाएगी या संभवतः वह बरबाद ही कर दी जाएगी।

परिवहन के साधन किसी  
 देश से जागृत जन-समुदाय  
 उपयोगी सिद्ध  
 (देश) को  
 सामाजिक

पद्धति में जकड़ा हुआ हो तो उनकी उपयोगिता सन्देहपूर्ण है।

भारत-जैसे देश में भी, जो इस अवस्थान पर पहुँच गया है, जहाँ वह काफी मात्रा में पूँजी का उपयोग कर सकता है, खतरे हैं। सम्भव है कि विदेशों से ऋण लेना विदेशों से धन कमाने के स्थान पर होता हो। विदेशों से धन कमाना दक्षतापूर्ण ढंग से तथा कम मूल्य पर उत्पादन करना है, जो अपेक्षाकृत अधिक विकसित अवस्थानों पर पहुँचे हुए देशों की इस प्रवृत्ति का लाभ उठा सकता है कि वे, कीनेस ने जैसा एक बार कहा था, "ऊँचे मूल्य, ऊँचा जीवन-स्तर" वाले देश बनना चाहते हैं। भारत के किसी भी मित्र को उसके गत पाँच वर्षों के अनुत्साहवर्द्धक निर्यात को देखकर चिन्ता ही होगी। औद्योगिकीकरण के लगभग इसी अवस्थान पर जब जापान था, तो उसके पास अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं को विश्व के बाजारों में येन-केन प्रकारेण भेजने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। इस कार्य का उद्देश्य सारे विश्व में लोकप्रियता प्राप्त करना नहीं था। परन्तु इसने उद्योग में लगाने के लिए पूँजी प्रदान की, जिससे उसका भाग भी विकास निश्चित हो गया। इसमें सन्देह है कि कोई भी सहायता, चाहे वह कितनी ही उदार शर्तों पर क्यों न हो, इस प्रकार की अर्जित पूँजी तथा तज्जनिता आत्मनिर्भरता एवं आत्मविकास का स्थान कभी भी ले सके।

. 4 .

शिल्प-ज्ञान का भी उधार लेना एक टेढ़ा मामला है। सैद्धान्तिक दृष्टि से वह बहुत ही यांछनीय है। विज्ञान-क्षेत्र में

पीछे रहने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि इस प्रकार का देश अपने से आगे वाले देशों द्वारा बड़े परिश्रम तथा मूल्य चुकाने के बाद सफलताओं, शिल्प-ज्ञान आदि से लाभ उठा सकता है। परन्तु, यह जानना तो आवश्यक होगा ही कि कोई शिल्प-ज्ञान, कोई सफलता क्यों और किस कारण से प्राप्त की गई। यह किसी प्रक्रिया में अगला कदम था या व्यापक प्रयोग का परिणाम था ? या वह आगे बड़े हुए स्वयं आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के प्रति अनुकूलोत्तरण था ? उन्नत पैदावार बाने सबके के बीज, धान रोपने की जायगी पद्धति विकसित आदों का प्रयोग, दम्भान उत्पादन का एल-डी तरीका, आदि व्यापक प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रणियाँ हैं। इनमें सभी माधनों का मितव्ययता में प्रयोग होता है। बेकम तथा अधिः विकसित दोनों ही प्रकार के देशों के लिए अनुकूल तथा महत्वपूर्ण हैं। परन्तु अपेक्षाकृत अधिक विकसित देशों का अधिसाग शिल्पज्ञान मर-दूरी की कमी की पूर्ति करने के लिए तथा अधिः विकसित अर्थ-व्यवस्था की विविष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही प्राप्त किया गया है। रई धुनने की मशीन तथा आधुनिक कृषि-ट्रैक्टर इस प्रकार के आविष्करण के उदाहरण हैं। अमे-रिका के कृषि-क्षेत्रों में उनका प्रयोग यह प्रकट करता है कि यही मरदूरी की भारी कमी है। इस प्रकार का शिल्प-ज्ञान उन लोगों को नहीं बनाना चाहिए, जो विकास के प्रारम्भिक अव-स्थानों पर हों। ऐसा करना अन्य माधनों को बरबाद करना है तथा विकास में बाधा डालना है और प्रागदिक रूप की अपेक्षा बहुत अधिः अग्रगण्य रूप में देवारी को बढ़ाना है।



पदवि में नरका हुआ हो तो उनकी उत्पादितता मन्देष्टुन है।

भारत-जैसे देश में भी, जो इस अवस्थान पर पहुँच गया है, जहाँ यह बारी मास में पूँजी का उपयोग कर सकता है, मन्देष्टु है। मध्यम है कि विदेशों में 'हृष्ट' जेना विदेशों में धन कमाने के स्थान पर होता हो। विदेशों में धन कमाना दशतापूर्ण रूप में तथा कम मूल्य पर उत्पादन करना है, जो संवेष्टाकृत अधिक विनिगित अवस्थानों पर पहुँचें हुए देशों की इस प्रवृत्ति का सामना उदा गकता है कि में, बीनेम में जेना एक बार कहा था, "ऊँचे मूल्य, ऊँचा जीवन-स्तर" माने देश बनना चाहते हैं। भारत के किमी भी मिन को उनके माता-पिता की के अनुदमाह्वयक निर्मात को देना चाहते हैं। शीर्षाधिकीकरण के लगभग इसी अवस्थान पर जब जागृत था, तो उनके पास अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं की विदेश के बाजारों में बेचने-क्रेन प्रकारेण भेजने के प्रतिरिक्त अन्य कोई चारा नहीं था। इस कार्य का उद्देश्य सारे विदेश में लोकप्रियता प्राप्त करना नहीं था। परन्तु इसने उद्योग में लगाने के लिए पूँजी प्रदान की, जिससे उसका भाग भी विकास निश्चित हो गया। इसमें सन्देह है कि कोई भी सहायता, चाहे वह कितनी ही उदार शर्तों पर क्यों न हो, इस प्रकार की अर्जित पूँजी तथा सज्जनित आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का स्थान कभी भी ले सके।

(ब्रिटिश औद्योगिक नगर) कोई नई अच्छी वस्तु तैयार करता है, वैसे ही सोनिगन (जर्मन नगर) भी उसी वस्तु को उससे सस्ते प्रतिमान के रूप में तैयार कर देता है। उसके बाद हाल में जापानियों तथा रूसियों की भी इसी प्रकार आलोचना की गई है। परन्तु बाद में धान वाले देशों को किसी बात की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। उन्हें बिना किसी सकोच के उन कार्य-पद्धतियों में लाभ उठाना चाहिए जो उनके पूर्वगमियों ने प्रथम बार निर्धारित की। बाद में पहुँचने के लाभ बहुत कम हैं। परन्तु जो हैं, उनका पूर्णरूपेण उपयोग किया जाना चाहिए।

### II

इतना तो मैंने पूँजी तथा शिल्प-ज्ञान उधार लेने के सम्बन्ध में कहा। अब मैं संघटन उधार लेने के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। संघटन से मोटे तौर पर मेरा तात्पर्य सरकार तथा उसकी सेवाओं, और शिक्षा, कल्याण एवं आर्थिक संघटन से है। मेरे विचार से इस क्षेत्र में सबसे अधिक खतरा है। इस प्रकार का उधार लेना अब बड़ी साधारण-सी बात बन गई है। चूँकि कोई विशेष संघटन या सेवा—कोई सरकारी विभाग, शिक्षा संस्था, या कृषि अथवा औद्योगिक सेवा—किसी अधिक विकसित देश में रहती है, यह सोच लिया जाता है कि वह विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अतः उसे कम विकसित देशों में भी स्थापित किया जाना चाहिए। यह उनके भी विकास में सहायक होगी।

इस प्रकार के तर्क से, यदि इसे तर्क कहा जाय, बहुत-सी गलतियों की संभावना है। बहुधा ही, और मैं तो कहूँगा कि

अतः अपेक्षाकृत अधिक विकसित देशों की नकल करना बुद्धिमत्तापूर्ण विकास-आयोजन का लक्षण है। और ऐसा न करना भी बुद्धिमत्तापूर्ण आयोजन का लक्षण है। व्यापक प्रयोग के आविष्करणों तथा केवल विकास के उच्च अवस्थानों के लिए ही उपयुक्त आविष्करणों में, जो मैंने ऊपर भेद बतलाया है, उसका प्रयोग करना आसान नहीं है। परन्तु यदि यह कम-से-कम मान लिया जाए कि विभेदीकरण आवश्यक है, तो उसका प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक सम्भव हो सकता है। बहुत दिन की बात नहीं है, एशिया के एक पड़ोसी देश में, जहाँ बेकारी बहुत है और मजदूरों को वेतन बहुत कम मिलते हैं, मैंने रेलवे-क्रॉसिंग पर विदेश से भगाए गए कीमती स्वचालित फाटक लगाए जाते देखा। इस प्रकार की विकसित वस्तुओं का प्रयोग उन देशों में आवश्यक है, जहाँ रेलवे फाटक के सन्तरी का मननपूर्ण जीवन बिताने के लिए भ्रम कोई मिलता ही नहीं। परन्तु उस देश में इस वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। जो भेद मैं बता रहा हूँ, उसे यदि और भी स्पष्ट रूप से विचार में रखा गया होता, तो काफी पैसा बच गया होता, और बेचारे फाटक सन्तरी दुआएँ देते हुए अपने पदों पर बने रहे होते।

जहाँ नकल करना उचित हो, वहाँ उसे धड़ल्ले से तथा बिना किसी संकोच के किया जाना चाहिए। अपेक्षाकृत अधिक विकसित देश उनकी सराहना नहीं करेंगे; वे बहुधा ही यह सोचते हैं कि नवागन्तुक का इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं। विगत शताब्दी में अंग्रेजों ने जर्मनों को नकल करने की प्रवृत्ति की बड़े कटु शब्दों में आलोचना की; जैसे ही शेफील्ड

(ब्रिटिश औद्योगिक नगर) कोई नई अच्छी वस्तु तैयार करता है, वैसे ही मोनिगन (जर्मन नगर) भी उसी वस्तु को उससे सस्ते प्रतिमान के रूप में तैयार कर देता है। उसके बाद हाल में जापानियों तथा रूसियों की भी इसी प्रकार आलोचना की गई है। परन्तु बाद में आने वाले देशों को किसी बात की चिन्ता नहीं करना चाहिए। उन्हें बिना किसी सकोच के उन कार्य-पद्धतियों में लाभ उठाना चाहिए जो उनके पूर्वगमियों ने प्रथम बार निर्धारित की। बाद में पहुँचने के लाभ बहुत कम हैं। परन्तु जो हैं, उनका पूर्णरूपेण उपयोग किया जाना चाहिए।

. 5

इतना तो मैंने पूँजी तथा शिल्प-ज्ञान उधार लेने के सम्बन्ध में कहा। अब मैं संपदन उधार लेने के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा। संपदन से मोटे तौर पर मेरा तात्पर्य सरकार तथा उसकी सेवाओं, और शिक्षा, कल्याण एवं आर्थिक संपदन से है। मेरे विचार से इस क्षेत्र में सबसे अधिक खतरा है। इस प्रकार का उधार लेना अब बड़ी साधारण-सी बात बन गई है। चूँकि कोई विशेष संपदन या सेवा—कोई सरकारी विभाग, शिक्षा संस्था, या कृषि अथवा औद्योगिक सेवा—किसी अधिक विकसित देश में रहती है, यह सोच लिया जाता है कि वह विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है। अतः उसे कम विकसित देशों में भी स्थापित किया जाना चाहिए। यह उनके भी विकास में सहायक होगी।

इस प्रकार के तर्क से, यदि इसे तर्क कहा जाय, बहुत-सी शक्तियों की संभावना है। बहुधा ही, और मैं तो कहूँगा कि

सामान्यतः ही, किसी अधिक विकसित देश का संघटन और उसकी सेवाएँ उसके विकास की हेतु नहीं हैं, अपितु परिणाम हैं। वे तो यह दर्शाते हैं कि आगे बढ़े हुए विकास की आवश्यकताओं के अनुकूल उनकी स्थापना हुई है या विकास के उस स्तर द्वारा ही वे सम्भव हो सके हैं। बिना सोचे-समझे, अविवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार के संघटन का उधार लेना या देना विकास में सहायक नहीं होगा, अपितु वह उसमें बाधक होगा। भारत सरकार एक बहुधर्मी तथा बहुमुखी वस्तु है, जो इस बात की द्योतक है कि भारत ने विकास के अपने अवस्थान में अनेक कार्य करने योजना बना रखी है। किसी नवोदित अफ्रीकी राष्ट्र के लिए, जहाँ अभी काफी दिनों तक सीधे और आसान ही कार्य किए जाने चाहिए, भारत जैसा जटिल, बहुमुखी संघटन भारी दुर्भाग्य की बात होगी। अमेरिका के बहुत-से सरकारी, शिक्षा-सम्बन्धी, कृषि तथा औद्योगिक संघटन अमेरिका के विकास के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसलिए विद्यमान हैं कि अपेक्षाकृत बहुत आगे बढ़े हुए विकास के अवस्थान में वे आवश्यक हो जाते हैं या कभी-कभी इसलिए भी कि गैर महत्वपूर्ण वस्तु भी रखने में हम अमरीकी समर्थ हैं। यदि उन्हें भारत भेज दिया जाय, तो भारत के लिए भी यह दुर्भाग्य की बात होगी। यदि विज्ञान पैमाने पर शिक्षा पाठ्यक्रम, विशिष्ट प्रकार की शिक्षा मंजूर करें, बहुत आगे बढ़ी हुई कृषि-मेयाएँ तथा विभिन्न प्रकार की अनेक गारंटीकृत मेयाएँ अपने समय में पढ़ने ही पालू कर दी जायें, तो उनमें वे गायन तथा शक्तिशाली लगानी पड़ जाएंगी, जो विकास के लिए निराश आवश्यक हैं। हममें साम नहीं होगा, उन्हें नहीं

अवश्य होगी। अब मैं इसे और भी स्पष्ट करता हूँ।

आज से सौ वर्ष पहले अमेरिका में मिसिसिपी के मैदानों के विकास के लिए सर्वप्रथम एक ऐसी भूमि नीति की आवश्यकता थी, जो भूमि का बन्दोबस्त कर दे और उसे कृषि योग्य बना दे तथा एक ऐसी परिवहन प्रणाली स्थापित हो, जिसके अंतर्गत अनाज आदि बाजारों में पहुँच सके। इसके लिए सरकार ने भूमि का सर्वेक्षण किया, ऐसे सभी व्यक्तियों को उसने 160 एकड़ भूमि दे दी, जिन्होंने कुछ महीनों तक उस पर खेती करके अपनी नकलीपती सिद्ध कर दी थी; उसने नई रेल लाइनें खानू करने में भी सहायता की। इन प्रारम्भिक आवश्यकताओं की व्यवस्था हो जाने के बाद विकास द्रुत गति में आगे बढ़ा। निरुत्सुक यह हमारा सौभाग्य था कि उस समय तक सामुदायिक शिक्षा विरोध, अनाज विषी के विद्रोहकर्ता, पर के सम्बन्ध में मनाह देने वाले लोग, व्यवसाय-सम्बन्धी परामर्शक, संचारण विरोध या जन-भुरक्षा परामर्शक आदि अव्यवस्थित नहीं हुए थे। यदि ये रहे होते तो भूमि का बन्दोबस्त करने तथा रेल लाइन खानू करने के अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य से लोगों का ध्यान हट गया होता। और ये लोग जनता पर एक भार हो गए होते, जो उन्हें ढोने में समर्थ नहीं थी।

आज अमेरिका में इन विस्तृत सेवाओं का भार आमानी से घटन किया जा सकता है और हमारे विकास की वर्तमान स्थिति में

कम

है। यदि उन्हें अमेरिका

देवार और दहा

में आदि

विकास के उभी घबघान पर हुए होते ।

जो लोग गंपटन तथा सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में स्थानान्तरण चाहते हैं, उन्हीं पर इनकी उपयोगिता सिद्ध करने का दायित्व रहना चाहिए । जितना हम भोचते हैं, उससे कहीं अधिक यह नाजुक मामला है । यह हम लोगों के लिए, जो उधार लेते हैं, उनकी ही बड़ी भेतावनी है, जितनी इन लोगों के लिए, जो उधार लेते हैं और शायद उससे भी ज्यादा ।

## . 6 .

ऊपर मैंने उन बातों के सम्बन्ध में कहा है जिन्हें मैं विभिन्न राष्ट्रों को दृष्टि में रखने पर विकास समस्या के सम्बन्ध में बड़ी गलत धारणाएँ समझता हूँ । इन गलत धारणाओं को अनुभव के आधार पर अब हम सुधार सकते हैं । हमें इस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अब तक गलतियाँ क्यों हुई हैं । दरिद्रता तथा पिछड़ेपन को दूर करने के भारी प्रयत्न में जुट पड़ना एक बहुत ही कठिन काम है । इन्हें आसान बनाना आवश्यक था; और शायद यह अनिवार्य था कि आवश्यकता से अधिक आसान बनाने में गलतियाँ हो जाएँ । कार्य स्थगित कर देना तथा समस्या के सही रूप में आने की प्रतीक्षा करना और भी बड़ी गलती हुई होती; क्योंकि यदि हम इन पिछले वर्षों के अपने अनुभव से सीखें न होते, तो इस समय हम इतने चतुर न बने होते । और अनुभव काफी कुछ सिखाता है, यद्यपि, जैसा कि विख्यात लेखक आस्कर वाइल्ड ने एक बार कहा था, वह हमारी गलतियों का ही हमारे ही द्वारा दिया हुआ एक दूसरा नाम है ।

### 3

## विकास नियोजन का सिद्धान्त

आजकल आर्थिक तथा राजनीतिक विवादों में जितना 'नियोजन' शब्द का सिर्फ फंजन के लिए प्रयोग होता है, उतना शायद ही अन्य किसी शब्द का होता हो या यों कहिये, जितना कम सही प्रयोग उसका होता है, उतना शायद ही अन्य किसी शब्द का। शब्द का ठीक न प्रयोग करना सन् 1940-50 वाले दशक के प्रारम्भ में विख्यात ब्रिटिश सैनिक तथा दार्शनिक कर्नल ब्लिम्स द्वारा बड़े ही अच्छे ढंग से दर्शाया गया था, जो युद्धो-परान आर्थिक प्रगति के लिए वर्तमान विश्वव्यापी चिन्ता पर ध्यान देते हुए यह कहते हुए सुने गए थे। "यह सब नियोजन आदि केवल सर्वनाश ही ला सकता है। परन्तु सर्वनाश के सम्बन्ध में एक बात आप कह सकते हैं; वह भ्रवाध उद्योग के लिए वास्तविक कार्यक्षेत्र प्रदान करता है।"

इस गलत बोध का मुकाबला बहुत दिनों तक वे भावनाएँ भी करती रही, जिन्हें 'नियोजन' शब्द ने उभाड़ दिया था। कुछ लोग तो नियोजन को प्रगति के लिए अनिवार्य मानते थे। औरों के लिए यह बुराई का मूल था। बहुत-से संघटन तथा राजनीतिक



दल नियोजन का प्रतिपादन करने के लिए ही उत्पन्न हुए। कुछ अन्य उगका विरोध करने के लिए स्थापित हुए। द्वितीय महा-युद्ध की समाप्ति के चौदह ही दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के कुछ विद्वान एक ऐसा संघटन स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक पर्वत शिखर पर एकत्र हुए, जिसका लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन का विरोध करना हो। यह संघटन अपने उद्देश्य में बहुत आगे नहीं बढ़ सका, जिसका एक कारण, जैसा कि मुझे बतलाया गया है, यह था कि लोगों में इस बात पर सैद्धांतिक मतभेद हो गया कि आया जहाजी बड़े सरकारी सम्पत्ति हों या पट्टा-किराया के आधार पर वे गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा प्रदान किये जाएँ।

. 2 .

सच तो यह है कि नियोजन के सम्बन्ध में गलत धारणा काफी हद तक सुधारी जा सकती है। और जब हाल में लोग उसके वास्तविक अर्थ को अपेक्षाकृत अच्छी तरह समझने लगे हैं, तो विवाद का भावना-प्रधान अंश बहुत कुछ समाप्त हो गया है। आधुनिक तथा विकसित अर्थ-व्यवस्था में निश्चित रूप से यह स्थिरकरना पड़ता है कि साधनों—धन, भूमि, पूँजी, प्राकृतिक साधनों—का किस प्रकार समन्वय किया जाए कि वे उपयोगी सिद्ध हों। यह कार्य या उसका अधिकांश, मुक्त बाजार-व्यवस्था को सौंपा जा सकता है। इससे यह होगा कि ऊँची कीमतों तथा ऊँची कमाई की आशा के माध्यम द्वारा उपभोक्ता की आवश्यकताएँ उत्पादक को ज्ञात हो जाएँगी। मुक्त बाजार-व्यवस्था वृद्धि को

व्यापार में लगाने का कार्य, मजदूरों को भरती तथा उत्पादन उपक्रम का, जो आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करता है, सघटन प्रारम्भ कर देती है।

इसके स्थान पर साधनों का एक बहुत सीमित सघटन भी हो सकता है। इसके अन्तर्गत जो कार्य करने होते हैं, तथा जिन वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, उनके सम्बन्ध में निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाने हैं। फिर सरकार इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक अधिकार प्राप्त करती है। विनीत-विनीत तरह यह यह निर्दिष्ट कर लेती है कि श्रम, पूँजी तथा अन्य साधनों का उपयोग निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक हो उनके अनुकूल होगा। फिर वह ऐसे सघटन स्थापित करती है तथा अपने निर्देशन में उन्हें चलानी है जो मान न्यार करती है।

इस दूसरी बात के सम्बन्ध में कुछ धीरे बतना आवश्यक है। नियोजन के मिडान्त का आविर्भाव भी समाजवाद के मिडान्त के साथ ही बहुत कुछ मिले-जुले रूप में हो रहा, जो एक विशेष कारण है कि इतने दिनों तक मर-मराज्जवादी श्रेणियों में लोग 'नियोजन' शब्द पर नाश-भी मिकोने रहे। समाजवाद के मिडान्त ने स्वभावतः प्राकृतिक साधनों तथा पूँजी, कारखानों एवं भूमि, कुछ राजनीतिक आवश्यकताओं के अन्तर्गत रहने हुए, भी सार्वजनिक स्वामित्व पर बड़ा बल दिया। यह दृष्टिकोण आवश्यक समझा गया कि मोरो का दोष नहीं हो सके, लोगों के सामाजिक स्वायत्त मिल सके तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के द्वारा हथियाने ली जाए। नियोजन के प्राकृतिक दृष्टिकोण के विकास के साथ ही साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व बढ़ा दिया।

अथ उनके नियोजित प्रयोग के लिए आवश्यक तथा यथेष्ट भी समझा जाने लगा । यदि सार्वजनिक स्वामित्व रहेगा तो नियोजन हो सकता है, और बिना सार्वजनिक स्वामित्व के प्रभावकारी नियोजन हो ही नहीं सकता ।

वस्तुतः, जैसा कि समाज-विज्ञानों के सम्बन्ध में बहुधा ही होता है, हमारे समक्ष जो विभिन्नताएँ हैं, वे इतनी गहरी नहीं हैं, जितनी दिन-प्रति-दिन के विवाद, विचार-विमर्श में वे बतलाई जाती हैं । उन देशों में, जो मुक्त बाजार-व्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, ऐसा होने के बावजूद, एक काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा होता है, जिनमें साधनों का संघटन सरकार द्वारा किया जाता है । यदि हम सभी वर्तमान साधनों के—समूचा राष्ट्रीय उत्पादन—जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित तथा व्यवस्थित है, अनुपात को नियोजन की मात्रा का मापदण्ड मान लें, तो हम यह देखेंगे कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का लगभग 20 प्रतिशत नियोजित होता है । भारत के मामले में यह 13-14 प्रतिशत ही होगा । अमेरिका की बाजार (मुख्य, गैर-समाज-वादी) अर्थ-व्यवस्था में भारत की समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है । और यह बालू रेत सरासरी है । हमें, जबकि उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, मजदूरों तथा माणिकों को बड़ी बुद्धिमत्ता से धन-सम्बन्धी बहुत-से प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं । निजी तौर पर उत्पादित कृषि-सामग्रियों का बाजार मात्रा में 77-विषय भी होता है । पौष्टिक तथा सूक्ष्मजीविकी में भी सार्वजनिक तौर पर कृषि मुख्य बाजार-व्यवस्था के ही अधीन है ।

कुछ सप्ताह पहले राष्ट्रपति केनेडी ने मनुष्य को चन्द्रलोक तक भेजने के लिए सुनिश्चित अनेक उपायों में से पहले उपाय की घोषणा की। अपने अधिकांश देशवासियों की भांति, श्रीर मेरा ख्याल है अन्य देशों की भी अधिकांश जनता की भांति, मैं इस माहमिक कार्य के प्रति थोड़ा कुतूहल अनुभव करने लगा हूँ। परन्तु यह एक ऐसी यात्रा नहीं है, जो शीघ्र ही इस आधार पर खालू हो जाए कि पेंसा दीजिए, टिकट कटाइए और खाना हो जाए। प्रारम्भ में एक टिकट का मूल्य कई अरब डॉलर होगा, जो किसी सामान्य यात्री की शक्ति से परे है। इसलिए यह कार्य निजी व्यापार-क्षेत्र के मध्ये नहीं छोड़ा जा सकता, वह तो केवल नियोजन में ही हो सकता है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के नियोजित क्षेत्र में ही आणविक शक्ति का भी उत्पादन हुआ और उसीके द्वारा आधुनिकतम विद्युत्-विमान भी विकसित हुआ। इसी प्रकार आधुनिक जेट विमान भी नियोजित विकास का ही परिणाम है, जो सैनिक सामान जुटाने की प्रक्रिया में एक उप-उत्पादन के रूप में आया। गैर-नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में गत कुछ वर्षों में जो अन्य मशीन-अवयवों का विप्लार हुए हैं, उनमें बहुतों का प्रादुर्भाव इसी प्रकार हुआ है। नियोजन में, सार्वजनिक स्वामित्व न रहने हुए भी, सार्वजनिक प्रेरक प्रतिभा उपलब्ध रहती है। अब दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण नहीं रह गया है।

. 3 .

मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं कि नियोजित तथा गैर-

अथ उनके नियोजित प्रयोग के लिए आवश्यक तथा यथेष्ट भी समझा जाने लगा। यदि सार्वजनिक स्वामित्व रहेगा तो नियोजन हो सकता है, और बिना सार्वजनिक स्वामित्व के प्रभावकारी नियोजन हो ही नहीं सकता।

वस्तुतः, जैसा कि समाज-विज्ञानों के सम्बन्ध में बहुधा ही होता है, हमारे समक्ष जो विभिन्नताएँ हैं, वे इतनी गहरी नहीं हैं, जितनी दिन-प्रति-दिन के विवाद, विचार-विमर्श में वे बतलाई जाती हैं। उन देशों में, जो मुक्त बाजार-व्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, ऐसा होने के बावजूद, एक काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा होता है, जिनमें साधनों का संघटन सरकार द्वारा किया जाता है। यदि हम सभी वर्तमान साधनों के—समूचा राष्ट्रीय उत्पादन—जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित तथा व्यवस्थित है, अनुपात को नियोजन की मात्रा का मापदण्ड मान लें, तो हम यह देखेंगे कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का लगभग 20 प्रतिशत नियोजित होता है। भारत के मामले में यह 13-14 प्रतिशत ही होगी। अमेरिका की बाजारू (मुक्त, गैर-समाजवादी) अर्थ-व्यवस्था में भारत की समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र है। और यह चालू रह सकता है। रुत में, जबकि उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, मजदूरों तथा मालिकों को बड़ी बुद्धिमत्ता, धन-सम्बन्धी बहुत-से प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। तौर पर उत्पादित कृषि-सामग्रियों का काफी मात्रा विनय भी होता है। पोर्तुगल तथा यूगोस्लाविया में भी तौर पर कृषि मुक्त बाजार-व्यवस्था के ही अधीन

खड़ा कर सकता है। इन सबसे भी महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि निजी व्यापार-क्षेत्र उन देशों में ऐसा करता है, जहाँ विकास पिछड़ गया है और जहाँ विकास की न केवल आवश्यकता है, अपितु यह परमावश्यक है कि वह सच हो। निजी व्यापार-क्षेत्र पर विश्वास करना यह अवाञ्छनीय खतरा मोल लेना है कि या तो कुछ नहीं होगा या होगा भी तो बहुत थोड़ा।

यही कारण है कि किसी विकासोन्मुख देश में नियोजन शब्द अब विवाद में परे हो गया है। पंचवर्षीय योजनाओं का आविष्कार सोवियत संघ ने किया है और एक समय था कि ये केवल सोवियत संघ में ही थी। अब अमरीकी तथा पश्चिमी यूरोप के लोग बिना कुछ सोचे-समझे यह विचार करने एकत्र हो जाते हैं कि वे भारत या पाकिस्तान की पंचवर्षीय योजनाओं में किस प्रकार वित्तीय सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे देश के सम्बन्ध में, जिनके सामने कोई लक्ष्य नहीं होते तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई निश्चित योजना नहीं होती, सामान्य धारणा यह होती है कि वह वित्कुल प्रगति नहीं कर सकता। सम्भवतः यह सही भी है।

#### 4.

चूँकि नियोजन को अब हमने एक तथ्य मान लिया है, हाल के वर्षों में उसके तरीकों में जो नये-नये विक्रम हुए हैं, उनके सम्बन्ध में हम उसी छानबीन नहीं करते जितनी करना चाहिए। पिछले दशक में मुझे इस प्रकार की अनेक योजनाओं की जाँच

करने का अवसर मिला है। और आगे की दुनिया में मुझे जवाब-देह के रूप में अनेक वर्षों तक रहना पड़ेगा जहाँ अपने पापों का उत्तर देने के लिए बहुत-से लोग पहले से ही हैं और जहाँ के सम्बन्ध में यह विदित है कि अर्थशास्त्रियों को उन सभी परामशों के लिए उत्तर देना पड़ता है, जो वे अपनी सरकारों को दिए रहते हैं। मुझे यह विश्वास हो गया है कि यह सोचना भारी गलती होगी कि नियोजन के सिद्धान्त और व्यवहार निष्पत्त भित्तियाँ हैं।

ऊपर मैं इस बात पर बल दे चुका हूँ कि हमें नियोजन-सम्बन्धी अपने कार्यक्रम किसी देश विशेष के विकास अवस्थान को ध्यान में रखकर ही निर्धारित करने चाहिए। विकास के प्रारम्भिक अवस्थानों में कोई योजना बनाना आर्थिक नियोजन के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त कार्य नहीं है। उसके लिए तो आधारभूत प्रशासकीय अवयवों का निर्माण करना, शैक्षिक तथा आधारभूत सांस्कृतिक ढाँचे का विकास करना तथा एक स्थायी और प्रगतिशील सामाजिक पद्धति का निर्माण करना उपयुक्त कार्य हैं। पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांसीसी तथा अमेरिकी के वाद जो इस प्रकार के कार्य किए गए, उनसे आर्थिक जीवन ने अपने विदेशी

कदम आवश्यक समझे गए।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विकास के प्रारम्भिक अवस्थानों में उत्पादन-लक्ष्य स्थिर करना तथा पूँजी लगाने के सम्बन्ध में योजना बनाना प्रयत्न कर्तव्य नहीं है। उल्टे, आवश्यक यह है कि इस विकास के लिए प्रणामकीय, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी पक्की नींव डाली जाए। आगे चलकर ही पूँजी लगाने के सम्बन्ध में कोई विस्तृत योजना बनाना उचित है। इस प्रकार का नियोजन, जैसा कि भारत तथा पाकिस्तान में हो रहा है, विकास के अपेक्षाकृत बड़े हुए अवस्थानों में होना चाहिए। अब मैं इस प्रकार के नियोजन के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा।

## . 5 .

आजकल की आदर्श विकास योजना पूँजी लगाने की ही योजना है। इनमें ये निर्णय व्यक्त किए हुए रहते हैं कि अल्प पूँजी-साधनों का अच्छा-से-अच्छा उपयोग क्योंकर किया जाए। इसका मुख्य लक्ष्य वह वस्तु प्राप्त करना होता है, जिसके सम्बन्ध में यह मान लिया जाता है कि पूँजी द्वारा वह प्राप्त हो सकती है, अर्थात् धार्मिक विकास की एक निश्चित तथा अनुमानित सन्तोषजनक गति। इस प्रकार के नियोजन में हम बात पर

८३

के विभिन्न अंगों में तान

अनुसार आगे-पीछे धावें।

कि जिस प्रकार के

उसी मात्रा में



नया उसी प्रकार का उत्पात तैयार होने और यह कि आवश्यकता नया पूंति के बीच यह संतुलन बराबर बना रहे। आर्थिक साधनों की पूंति के सम्बन्ध में भी उतना ही ध्यान रखा जाता है, अर्थात् हम प्रश्न पर कि देशी और विदेशी दोनों ही पूंजी कहाँ से आएगी। नियोजन का यह कार्य जिस ढंग से किया जाता है, उसके सम्बन्ध में, कम-से-कम सिद्धान्ततः तो कोई दोष नहीं जान पड़ता। परन्तु कुछ अन्य ऐसी चीजें हैं, जिनकी व्यवस्था तो किसी भी अच्छी योजना को करना ही चाहिए, और इनकी महत्ता सर्वदा याद्यनीय स्पष्टता से नहीं समझी जाती। अब मैं किसी अच्छी योजना की तीन बातों की चर्चा करता हूँ, जो इनके अनिवार्य हैं तथा जो बहुधा ही गायब रहती है।

पहले तो किसी भी अच्छी योजना में आर्थिक प्रगति के लिए एक विशेष विधि की व्यवस्था रहनी चाहिए। इस प्रकार की विधि में कुछ बातें तो परमावश्यक हैं, अर्थात् उपयोगी या अनावश्यक से भिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि स्वर्ग-दूतों के गुणों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इसी प्रकार यदि प्रत्येक वस्तु को महत्वपूर्ण समझा जाएगा तो वास्तव में जो महत्वपूर्ण है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। उदाहरण के लिए, किसी औद्योगिकीकृत देश में एक अत्यन्त कुशल परिवहन व्यवस्था, कम कीमत पर, उत्पात का उत्पादन तथा कम ही कीमत पर एवं विश्वसनीय विद्युत् शक्ति का साधन अनिवार्य वस्तुएँ हैं। इनके रहने पर यह निश्चित है कि कुछ-न-कुछ प्रगति अवश्य होगी; इनके न रहने पर हम उतना निश्चित नहीं हो सकते। औद्योगिकीकरण के कुछ अन्य पहलू उतने

नहीं है, भले ही वे अनावश्यक न हों। इसी प्रकार, कृषि में बहुत सी बातें उपयोगी भले ही हों, परन्तु कुछ बातें तो अनिवार्य होती हैं। पानी, खाद तथा उन्नत बीज कृषि में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकते हैं। कृषि-सम्बन्धी अधिकांश अन्य बातें थोड़ा-बहुत परिवर्तन ला सकती हैं।

इन अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों के विरुद्ध भिन्न-भिन्न व्यक्तियों, विभिन्न विभागों तथा विभिन्न क्षेत्रों का यह दबाव काम करता रहता है कि उनके मनोवांछित उपक्रम आधुनिक योजना में सम्मिलित कर लिए जाएँ। यह दबाव बहुत भारी होता है। यह इच्छा भी उत्कट रहती है कि कोई बात छूट न जाय। इस प्रकार योजना योजना नहीं रह जाती, अपितु उन सारी बातों की मात्र एक सूची हो जाती है, जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति पूरा किया चाहता है या कोई भी सोचता है कि उन्हें कर लेना चाहिए। महत्वपूर्ण आवश्यकता की बातों का निश्चित रूप में निर्धारण करना रह ही जाता है।

स्वतन्त्रता के पहले, अमरीकी उपनिवेशों में तथा गणराज्य स्थापित हो जाने के बाद भी प्रारम्भिक वर्षों में वही खाद्यान्नों का कोई बाहुल्य नहीं था। पर्यन्तों तथा सागर के बीच की भूमि सीमित थी और वह सभी जगह उपजाऊ नहीं थी। कभी-कभी खाद्यान्नों तथा मवेशियों के लिए चारे की माँग उत्पादन-क्षमता से अधिक हो जाती थी और खाद्यान्न यूरोप से मगाने पड़ने थे। प्रारम्भिक अमरीकी कृषि के लिए आधुनिक तरीके पर बना हुई किसी योजना में कृषि बँतियों, विस्तार सेवाओं, पशु सेवाओं, पौधों के प्रजनन, अच्छी हाट-व्यवस्था, बीटों की रोकथाम तथा

अतिरिक्त भाण्डार के रखने की व्यवस्था पर बल देना पड़ता। निस्सन्देह किसी अच्छी परिवहन-व्यवस्था की आवश्यकता की भी चर्चा की गई होती। परन्तु अन्य अच्छी तथा उपयोगी बातों की तुलना में इसकी आसानी से उपेक्षा की जा सकती थी। सन् 1825 ई० में न्यूयार्क राज्य ने एक नहर खोली, जिसने पश्चिमी प्रदेश के ग्रन्थ इलाके को आयादी वाले भाग से मिला दिया। नहर बनते ही स्राव की कमी समाप्त हो गई और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। यह नहर उस योजना की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। सर्वाधिक महत्व की चीजों को चुनने तथा उन पर बल देने का महत्व आज के किसी विकासोन्मुख देश में उतना ही है।

### . 6 .

किसी अच्छी योजना की दूसरी आवश्यकता यह है कि वह औद्योगिक सफलता के दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही पहलुओं पर चल दे। किसी आधुनिक औद्योगिक समाज का वृहत्तर भाग, पानी में तैरने वाले एक हिमशैल की भाँति, दृष्टि से ओझल ही रहता है। और, हिमशैल ही की भाँति, उसके अदृश्य भाग में ही किसी जहाज में टक्कर मारकर उसे डुबाने की अधिक क्षमता होती है। बड़ी-बड़ी मशीनों के कारखाने तैयार करना तथा बड़े-बड़े उद्योग खड़े करना, जैसे इस्पात के कारखाने, रेल लाइनों, कोयले की खानें, वायुयान, तेलशोधक यन्त्र आदि विकास-योजना की दृश्य सफलता है। और यह देखना कि इन सब कारखानों, उद्योगों के

यह देखना कि व्यवस्था विभाग किसी पर आश्रित नहीं है और दक्ष है, कि फलतः उत्पादन सामग्रियों के मूल्य कम हैं तथा कारखाने के नवीनीकरण एवं विस्तार के लिए पर्याप्त कमाई हो रही है—समूचे कार्य का बृहत्तर भाग है। यह भाग सतह से नीचे रहता है, और इतना ही काफी नहीं है कि विकासोन्मुख देश केवल इन्हीं बातों में परिपूर्ण हो। उसे अवश्याकृत आगे बढ़े हुए अपने प्रतियोगियों से अधिक उत्पादनशील होना चाहिए। कम उत्पादन तथा दक्षतापूर्ण उत्पादन द्वारा ही जर्मनी और जापान औद्योगिक दुनिया में अपने से आगे हुए देशों की समता में आगे बढ़ गए। इजरायल तथा यूगोस्लाविया जैसे नये औद्योगिक देश भी इसी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी तरीके से ही और भी आगे बढ़ने के लिए देशी और विदेशी दोनों ही पूंजी अर्जित की जाती हैं।

मैं इसे बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूँ कि प्राधुनिक योजनाएँ इस अद्भुत सफलता के लिए पक्के लक्ष्य निर्धारित कर लें। उत्पादन के लिए ठोस लक्ष्य निर्धारित करना जितना आवश्यक है, उतना ही श्रमघण्टे की उत्पादन क्षमता, उत्पादन कीमतों तथा प्रतिफलों के लिए भी ठोस लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना मध्य-गणित लोगों के लिए आवश्यक हो जाता है। उन्हें पूरा करने के लिए सभी को एक प्रकार की चुनौती मिल जाती है। यदि निर्दिष्ट कार्य पूरा करने में कोई कमी हुई तो सभी लोग इसे अपनी क्षमता समझेंगे। इसके अनिश्चित, इसमें यह अत्यन्त व्यावहारिक बात भी तो है कि क्षमता के लिए उत्तरदायी

अतिरिक्त भाण्डार के रखने की व्यवस्था पर बल देना पड़ता। निस्सन्देह किसी अच्छी परिवहन-व्यवस्था की आवश्यकता की भी चर्चा की गई होती। परन्तु अन्य अच्छी तथा उपयोगी बातों की तुलना में इसकी आसानी से उपेक्षा की जा सकती थी। सन् 1825 ई० में न्यूयार्क राज्य ने एक नहर खोली, जिसने पश्चिमी प्रदेश के अन्ध इलाके को आवादी वाले भाग से मिला दिया। नहर बनते ही खाद्य की कमी समाप्त हो गई और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि फिर ऐसा कभी नहीं हुआ। यह नहर उस योजना की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी। सर्वाधिक महत्व की चीजों को चुनने तथा उन पर बल देने का महत्व आज के किसी विकासोन्मुख देश में उतना ही है।

. 6 .

किसी अच्छी योजना की दूसरी आवश्यकता यह है कि यह औद्योगिक सफलता के दृश्य तथा अदृश्य दोनों ही पहलुओं पर बल दे। किसी आधुनिक औद्योगिक समाज का बृहत्तर भाग, पानी में तैरने वाले एक हिमशैल की भाँति, दृष्टि से ओझल ही रहता है। और, हिमशैल ही की भाँति, उसके अदृश्य भाग में ही जहाज में टक्कर मारकर उसे डुबोने की अधिक क्षमता है। बड़ी-बड़ी मशीनों के कारखाने तैयार करना तथा उद्योग खड़े करना, जैसे इस्पात के कारखाने, रेल की खानें, वायुयान, तेलशोधक यन्त्र आदि दृश्य सफलता है। और यह देना कि उद्योगों आदि का उपयोगी एवं कुशल ढंग से



की उचित आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति यथासम्भव सस्ते ढंग से कर सके ?

यदि इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार नहीं किया जाता तो सम्भव है कि उनका उत्तर बिना सोचे-समझे ही दे दिया जाए। विशेषकर इस बात का खतरा है कि अपेक्षाकृत अधिक विकसित देशों की उपभोग प्रणाली का सीधे अनुसरण कर लिया जाए। सम्मान तथा गौरव की इच्छा भी, जैसे टेलीविजन एवं अत्यन्त चौड़े राजपथों का निर्माण एवं दिखावा, इसे प्रभावित कर सकती है। उपभोग का सिद्धान्त इसकी अपेक्षा अधिक लोक-तन्त्रीय होना चाहिए। उन वस्तुओं पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए जो सामान्य आय की हैसियत में हों, अर्थात् जो किमी सामान्य औसत परिवार द्वारा खरीदी जा सकें। इसे सिद्ध करने का उत्तरदायित्व अन्य लोगों पर है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी कम आय वाले देश के लिए सस्ती वाइसिकिलें सस्ती मोटरों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं। गाँवों में रोशनी प्रदान करने के लिए कोई कम खर्च वाली विद्युत् पद्धति किसी बहुत अधिक विजली उत्पादन करने वाली पद्धति से, जिसमें ऐसे साज-सामानों की आवश्यकता होती है, जो जनता की शक्ति के परे होते हैं, कहीं अच्छा है। कम खर्च वाले रेडियो महत्वपूर्ण हैं, टेलीविजन तो भविष्य में भी प्रा-  
प्त है। और अन्त में, प्रचुर मात्रा में भोजन, वस्त्र तथा रहने के लिए उचित स्थान जितने आवश्यक हैं, उतनी अन्य कोई वस्तु नहीं, क्योंकि ये वस्तुएँ तो सर्वसाधारण की आवश्यकताएँ

मुझे यह कहते प्रसन्नता होती है कि सर्वसाधारण की आवश्यकता को ही दृष्टि में रखकर उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन की योजना बनाने में भारत जितना आगे गया है उतना अन्य कोई विकासोन्मुख देश नहीं। परन्तु सभी विकासोन्मुख देशों में यह आवश्यक है कि हम बहुत स्पष्ट रूप से उस उपभोक्ता को ही अपनी दृष्टि के समक्ष रखें, जिसके लिए ही अन्ततोगत्वा नियोजन होता है।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, इसे निर्धारित कर लेना औद्योगिक सफलता की अदृश्य तथा दृश्य दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति की विन्ता करना, तथा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसे स्पष्ट रूप में समझ लेना—मेरे विचार से आधुनिक विकास नियोजन में इन्हीं बातों की कमी है।



## शिक्षा एवं आर्थिक विकास

चूँकि पिछले कुछ वर्षों में एशिया तथा अफ्रीका के बहुत-से नये देश उपनिवेशवाद के बन्धन से मुक्त हुए हैं और वहाँ के लोग श्रेष्ठ नागरिक के रूप में अपने राष्ट्रीय विकास के काम में जुट गए हैं, उन्हें यह निर्णय करना पड़ा है कि शिक्षा विस्तार में पैसा लगाने की क्या प्राथमिकता दी जाय। क्या उसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए? क्या अन्य सभी बातों में प्रगति के लिए शिक्षा अनिवार्य है? या, पहले एक आर्थिक भित्ति तैयार की जाए? जब उत्पादन आय बढ़ती है तभी अच्छी शिक्षा सम्भव हो सकती है। इसीसे स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के चलाने के लिए साधन उपलब्ध हो सकने हैं। स्कूलों तथा शिक्षकों आदि का व्यय वहन करने के लिए किसी राष्ट्र का आर्थिक विकास आवश्यक है।

इन प्रकार के वाद-विवाद हुए हैं। सभी बर्गों ने ऐसा भी दृष्टा है कि निर्णय भी हो गया और किसी ने यह नहीं देखा कि उनमें कोई विवाद भी था। शिक्षा को प्राथमिकता दे दी गई। या व्यय के सन्दर्भ में—गृहों, फार्म, मशीनों, बीघों—को प्राथमिकता दे दी गई, क्योंकि उन्हें मशीनों का बन्धन सम्भव नहीं था।

प्राथमिकता की यह समस्या अपेक्षाकृत नई है। अर्थशास्त्र के साथ ही अनिश्चितता का भी प्रवेश हो गया है। आजकल आर्थिक विकास को पूर्णतः आर्थिक विश्लेषण की ही समस्या मान लिया गया है। और आर्थिक विश्लेषण में शिक्षा का स्थान अस्पष्ट है। इस अस्पष्टता के कारण इस सम्बन्ध में यह सन्देह तथा अनिश्चितता उत्पन्न हो गई है कि किस बात को प्राथमिकता दी जाय।

. 2 .

इसे और स्पष्ट कहा जाय तो बात यह है कि हम भविष्य के अधिक उत्पादन के लिए अपने वर्तमान साधनों के प्रयोग, अथवा यों कहिये कि प्रगति के लिए वचन के प्रयोग को ही आर्थिक विकास समझने लगे हैं। हम किसी देश का विकास प्रयत्न उसके द्वारा विविध कार्यों में लगाई जाने वाली पूँजी की मात्रा से ही आँकते हैं, अर्थात् इस बात से आँकते हैं कि वह भविष्य की उत्पादन-वृद्धि की इच्छा से प्रेरित होकर पूँजी लगाने के लिए स्वयं अपने उपभोग में कितना बचाता है तथा विदेशों से कितना ऋण ले रहा है। यही पर समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि शिक्षा एक प्रकार का उपभोग और एक प्रकार का धन विनियोग दोनों ही है। रोटी की तरह वह एक ऐसी चीज है, जिसका हम उपयोग या उपभोग करते हैं। परन्तु 'बाँध या नहर की तरह' वह एक ऐसी चीज है, जिसमें हम इसलिए पूँजी लगाते हैं कि भविष्य में अधिक उत्पादन हो। यही अन्तर विकास में शिक्षा के स्थान के सम्बन्ध में बहुत ही भिन्न दृष्टिकोण उत्पन्न कर देता है।

जब हम शिक्षा को एक उपभोक्ता सेवा मानते हैं, तो वह एक ऐसी वस्तु बन जाती है, जिस पर हमें बचाना चाहिए। पूँजी लगाने के लिए बचत करना आवश्यक है, और बचत तभी सम्भव है जब उपभोग में कमी की जाय। परन्तु जब हम शिक्षा को एक धन विनियोग मानते हैं, तो वह एक ऐसी वस्तु बन जाती है जिस पर हमें बल देना चाहिए। हम पूँजी में विस्तार करना चाहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नीति के सम्बन्ध में भारी द्वन्द्व उत्पन्न हो जाता है।


इस द्वन्द्व के मूल में जो परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं, वे शिक्षा सम्बन्धी लगभग प्रत्येक घात या चर्चा में स्पष्टतया दिस-लाई पड़ते हैं। सारे ससार के दीक्षान्त भाषणकर्ता अपने अत्यन्त उदासीन श्रोताओं को स्मरण दिलाते रहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी के ही बल पर जीवित नहीं रह सकता। मस्तिष्क को भी उर्वरा बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना शरीर का पोषण। बौद्धिक कार्य में केवल कार्य की ही खातिर लगे रहना उचित है; कवि, कलाकार या लेखक द्वारा अधिक लाभ की सफलता की कसौटी के रूप में धुणा करना न्यायोचित है। अधिक लेता-जोखा का आत्मा तथा मस्तिष्क की ताजगी के लिए प्रयोग किये जाने की भयंशास्त्रियों की प्रवृत्ति के ही कारण विख्यात लेखक कार्लाइल ने उन्हें शुष्क विज्ञान के विद्वान् प्रोफेसर बतनाया था। और इसे कौन सही मानेगा कि जनता को अज्ञान के अन्धकार से केवल इसलिए बाहर निकाला जाय कि वे अधिक उत्पादन करने लग जायें? इन दृष्टिकोणों में निशा का महत्व बेयग अपनी ही खातिर बतनाया गया है, अर्थात् मेरी टेड परिभाषा के

अनुसार, वह एक उपभोग्य वस्तु है। यद्यपि वह एक श्रेष्ठ उप-भोग्य वस्तु है, उत्पादन में उसका प्रत्यक्षत कोई सम्बन्ध नहीं। और वे लोग, जो समार के प्रति इतना आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते, स्वभावतः खाइयों, बाँधों तथा खाद कारखानों की प्राथमिकता दिये जाने पर बल देते हैं, क्योंकि ये ही तो कवियों, लेखकों आदि को भोजन प्रदान करते हैं।

इनके प्रतिरिक्त एक और भी दृष्टिकोण है। अमेरिका के बहुत से विद्वानों में से थोडोर लुज के विवेचनों ने हाल में यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा में लगाया गया धन उत्पादन में काफी वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार के हिसाब से, जिसे कार्ल-इल बहुत घृणा किये होते, मनुष्यों के बौद्धिक विकास में लगाया गया एक डालर या एक रुपया राष्ट्रीय आय में बहुधा जितनी वृद्धि कर सकता है, उतना रेलवे, बाँधों, मशीनों के मीजारों या मशीनरी आदि के अन्य मामलों पर लगाया गया डालर या रुपया नहीं कर सकता। कृषकों तथा ग्रामीणों को निरक्षरता से मुक्त करना निस्सन्देह स्वयं ही एक साध्य हो सकता है। परन्तु कृषि में किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए वह प्रथम और अनिवार्य कदम भी है। मसार में ऐसा कोई भी निरक्षर कृषक-वर्ग नहीं है, जो प्रगतिशील हो। साथ ही ऐसा पढ़ा-लिखा कृषक-वर्ग नहीं है, जो प्रगतिशील न हो। इस दृष्टि से देखने पर शिक्षा धन का अत्यन्त उपयोगी विनियोग बन जाती है।

यह बात अनेक प्रकार की शिक्षा के सम्बन्ध में सच है। हममें से अधिकांश इस बात से सहमत तो होंगे ही कि आर्थिक विकास के लिए वैज्ञानिक तथा इंजीनियर बहुत ही आवश्यक

हैं। मशीनों का अब उतना महत्व नहीं है, जितना उनके बनाने वालों का, उनकी देखभाल करने वालों का या उनमें सुधार करने वालों का। परन्तु डाक्टरों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य-विशेषज्ञों की उत्पादनशीलता भी बहुत ऊँची है। मलेरिया का सफाया कर देने से मानवीय शक्ति तथा तत्जनित उत्पादन में भारी वृद्धि हो जाती है, जैसाकि गत पन्द्रह वर्षों के अनुभव ने सिद्ध कर दिया है। (उससे बच्चों की पैदाइश में भी आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाती है और गत कुछ वर्षों में जब हम उधर गर्भ-निरोध की बात करते रहे हैं, इधर विज्ञान ने अब तक गर्भ-निरोध की दिशा में जो कुछ किया है, उससे कहीं अधिक सफलता उसे उसके उन्नयन में मिली है।) नीग्रो जाति के चर्म रोग तथा पेट में कीड़े वाले रोग के निरोध से भी उत्पादन-क्षमता पर यही असर पड़ा है।

परन्तु केवल वैज्ञानिक, इंजीनियर तथा डाक्टर ही शिक्षा-सम्बन्धी अच्छे धन विनियोग नहीं हैं। ज्ञान के कुछ विशिष्ट और यहाँ तक कि विदेशी स्वरूपों को भी आश्चर्यजनक प्रतिफल मिलते हैं। स्पष्ट है कि भाषाविद अन्य संस्कृतियों के शिल्प-विज्ञान से सम्पर्क स्थापित करने में सहायक होता है। साक्षरता बढ़ने पर लेखकों की माँग होती है, जो शिक्षित लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और सिद्ध लेखक राष्ट्रीय उत्पादन के सम्पूर्ण योग में ठीक उसी प्रकार वृद्धि करता है, जिस प्रकार एक सफल कृषक। धन विनियोग की वस्तु के रूप में कलाकार तक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आधुनिक भारत का एक    
— कला-निर्माण, चित्रकारों, संगीत, नृत्य।

सलित कलाओं में एक मुरझित कलापीपक परम्परा रहने पर ही यह उद्योग फूलता-फलता है। साधारण फिल्म बनाने के लिए भी साधारणतया अच्छे कलाकारों की आवश्यकता पड़ती है; और अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत ही अच्छे कलाकार चाहिए। किसी कलाकार की कला-सम्यग्धी शिक्षा-दीक्षा में किमी ने यह सोचकर कभी पैसा नहीं खर्च किया कि इससे देश के विदेशी ऋण भुगतान में सहायता मिलेगी। फिर भी भारत की कला-परम्परा विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सराहनीय कार्य कर रही है।

• 3 •

वास्तविकता यह है कि शिक्षा तुरन्त उपयोग की जाने वाली सामग्री के रूप में भी और अविव्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए धन विनियोग के रूप में भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह न तो केवल उपभोग है और न केवल धन विनियोग, अपितु दोनों ही है। किसी विकासोन्मुख देश में धन विनियोग को इतना महत्त्व दे देने के बाद शिक्षा को महत्त्व एक उपभोग्य वस्तु के रूप में देखना उगरी महत्ता को धनबिज्ञ रूप में कम करना दुष्टा। कुछ नए देशों ने ऐसा ही किया है। उन्होंने अपने इमान्दार कार-सानो, दाँधों तथा खाद कारखानों को अपने विकास का प्रतीक माना है। मिरर का घासवा, घाना का बोन्टा तथा भारत का भाषटा-नगल निश्चित रूप से विकास माने जाते हैं। उनके सम्बन्ध में बर्बादें चलती रहती हैं, उन पर धन लगाया जाता है, पर्यटकों को वे दिखाये जाते हैं, देश उन पर गर्व करता है।

भली-भाँति प्रशिक्षित शिक्षक भले ही भविष्य में उत्पादन की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतर आधार प्रदान कर दें, परन्तु वे प्रगति के ऐसे मूर्त चिह्न नहीं माने जाते।

परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि इस गलती का सुधार किया जाने लगा है, और मैं यहाँ यह कह देना चाहता हूँ कि भारत में यह गलती इतनी गम्भीर कभी नहीं हुई है, जितनी अन्य कम विकसित देशों में। आम तौर पर, भारत उन्नीसवीं शताब्दी के ही अनुभव पर अब भी चल रहा है, जो यह है कि शिक्षा या ईमानदार तथा सुव्यवस्थित सरकार द्वारा पोषित शिक्षा को प्रथम स्थान मिलना चाहिए। परन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि किसी भी देश ने शिक्षा को पूर्णतः विकास-धन विनियोग के रूप में मान लिया हो। विश्वविद्यालयों के न तो छात्रों ने और न प्रोफेसर्स ने अब तक अपनी इस महत्ता को भली-भाँति समझा है कि वे दुर्लभ विकास साधनों में धन विनियोग के एक स्वरूप हैं। अब मैं इस सम्बन्ध में ही कुछ कहता हूँ।

#### • ४ •

यदि शिक्षा (अब मैं विशिष्ट रूप से विश्वविद्यालयों की ही शिक्षा की बात करता हूँ) को एक उपभोक्ता सेवा मान लिया जाय तो स्वभावतः हम उसके सम्बन्ध में भी वे ही बातें सब मान लेंगे, जो उपभोग के अन्य स्वरूपों के लिए सही जान पड़ती हैं। इनमें भारी स्वच्छन्दता की भी एक बात है। 'उपभोक्ता की सम्मति' अर्थशास्त्र का एक बहुत पुराना मुहावरा है, जिसका तात्पर्य है कि उपभोक्ता को उपभोग के विभिन्न

स्वरूपों में से चुनने का पूर्ण अधिकार है। और तो और, उसे इस बात की भी पूरी छूट है कि वह उपभोग करे या न करे।

उपभोक्ता संप्रभुता की इस धारणा को यदि शिक्षा पर लागू किया जाय, तो इसका अर्थ यह हुआ कि विद्यार्थी को यह अधिकार है कि वह पढ़े या न पढ़े, जिस प्रकार उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह उपभोग करे या न करे। इसका अर्थ यह भी हुआ कि पढ़ना या न पढ़ना व्यक्ति की और केवल व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि पढ़ने का क्षेत्र भी उसकी रुचि पर निर्भर है। इन मामलों में उसकी संप्रभु इच्छा में किसी को हस्तक्षेप करने या उसका पथ-प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। परन्तु यदि वास्तव में विद्यार्थी दुर्लभ साधनों के घन विनियोग की एक विशिष्ट वस्तु है, फिर तो बात इतनी साफ नहीं है। समाज ने उसे अपनी वचत का कुछ भाग दिया है। निश्चय ही उसका यह कर्तव्य हो जाता है कि इसके बदले वह उत्पादन-वृद्धि में योग दे, वापस करे, जिसकी समाज उससे अपेक्षा करता है और जिसके लिए उसने अपना दुर्लभ साधन व्यय किया है। साधनों की मात्रा जितनी ही कम होगी, उसी अनुपात में उसका दायित्व बढ़ा होगा।

जैसा कि मैंने कहा है, यदि शिक्षा को एक उपभोग्य सामग्री के रूप में देखा जायगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार पाठ्यक्रम चुनने का अधिकार होगा। प्रत्येक व्यक्ति को कला में ही डिग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा, यदि वही अध्ययन का आमतौर पर वांछित तथा फंशनेबल पाठ्यक्रम हो। परन्तु



यदि शिक्षा एक प्रकार का धन विनियोग है, तो शिक्षा से प्राप्त प्रतिफल का नियोजन श्रेयस्कर एवं अनिवार्य भी है। देश की उपलब्ध प्रतिभा का इंजीनियरिंग, विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र, कृषि तथा अन्य आवश्यक विशिष्ट क्षेत्रों में वितरित करने पर ध्यान देना आवश्यक है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के प्रतिकूल पेशे में जाने के लिए बाध्य किया जाय। और विश्वविद्यालयों में विशेष विषयों की पढ़ाई का नियोजन तो एक अत्यन्त कठिन मामला है। परन्तु मेरे कहने का तात्पर्य यह अवश्य है कि यदि शिक्षा को धन विनियोग का एक रूप मान लिया जाता है, तो आवश्यकता, प्रोत्साहनों तथा अन्य बातों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करके ही विद्यार्थियों के विषयों का चयन किया जाय, जिससे धन विनियोग का उद्देश्य पूरा हो सके।

### . 5 .

शिक्षा को धन विनियोग के रूप में देखने का प्रभाव, मेरे विचार से, विश्वविद्यालयों के संचालन तथा प्रशासन पर भी पड़ेगा। विश्वविद्यालयों को विकास की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियात्मक होना चाहिए तथा उनका संघटन ऐसा होना चाहिए कि यह सम्भव हो सके। इसका अर्थ हुआ कि वहाँ के शिक्षक वर्ग तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधि एक दृढ़ तथा प्रतिक्रियात्मक नेतृत्व प्रदान करें। जन-समुदाय की आवश्यकताओं का पाठ्यक्रमों, पढ़ाये जाने वाले विषयों तथा अच्छे शैक्षिक अनुशासन में मेलो-मेलि सम्भावित हो जाना चाहिए। सोकत

के विरुद्ध कुछ कहना या उसके विरोधी पक्ष का समर्थन करना बड़ा कठिन है। परन्तु अच्छा से अच्छा स्कूल मास्टर और अच्छे से अच्छे लोकतंत्रीय देशों में हमेशा ही एक निरंकुश व्यक्ति रहा है। कोई विश्वविद्यालय जब तक अपने शिक्षकों के हाथ में व्यापक एवं दायित्वपूर्ण अधिकार नहीं सौंपता और आवश्यकता पड़ने पर जब तक शिक्षक वर्ग अपने प्रतिनिधियों को नहीं सौंपता, तब तक विश्वविद्यालय का पूर्णतः सफल होना सम्बन्धपूर्ण है। पिछले कुछ समय से दक्षिणी अमेरिका के विश्वविद्यालय अपने यहाँ बहुत ही लोकतंत्रीय संचालन का, जिसमें विद्यार्थी, स्नातक तथा शिक्षक वर्ग सभी लगभग समान रूप में भाग लेते हैं, प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्रीय हो या न हो, यह योजना अचूक, असमझस्य एवं गड़बड़ी को हेतु अवश्य है। मेरे विचार में विश्व-विद्यालय स्वभाव से ही अपने शिक्षक वर्ग का एक अन्तर्जनन है। उस सूरत में तो उसे निश्चय ही ऐसा होना होगा, यदि शिक्षा को एक लाभपूर्ण धन विनियोग समझकर उसमें अधिकाधिक वांछित सदस्यों की प्राप्ति अपेक्षित है।

## . 6 .

परन्तु मैं शिक्षकवर्ग की भी समालोचना किन्ने दिना नहीं रह सकता। जब शिक्षा विभाज्य के लिए एक धन विनियोग मान ली जाती है, तो शिक्षकवर्ग पर भी कुछ विशेष दायित्व पड़ा जाते हैं। यह किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता कि विश्वविद्यालयों की परम्परागत शक्तें एवं आचार आदि विभागोन्मुख देश की आवश्यकताओं के अनुकूल होने हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश

पुराने विषयविद्यालयों में, जैसाकि मेरा भी विश्वविद्यालय है, बहुत से शिक्षक प्रशिक्षण कार्य को अत्यन्त उच्च कार्य मानकर उसके प्रति एक दम्भपूर्ण धारणा रखने लगे हैं। हम कहते हैं कि हमारा मुख्य कार्य अनुसन्धान करना या पुस्तकें आदि लिखना या बौद्धिक रूप से नेतृत्व करना है। हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों को इससे ही पर्याप्त लाभ हो जाता है कि वे हमें सड़क पर जाते हुए देख लें या सप्ताह में केवल तीन बार बेजान तथा लड़खड़ाती भाषा में बोले गये हमारे भाषण सुन लें। यदि शिक्षा की कसौटी उत्पादन-क्षमता है, तो इन दृष्टिकोणों के लिए कोई स्थान नहीं। फिर तो शिक्षक का कार्य अपने छात्रों को ऐसा रूप देना है, उनका इस प्रकार पथ-प्रदर्शन करना है तथा उन्हें इस प्रकार प्रोत्साहित करना है कि वे वास्तव में अधिक उत्पादक सम्पत्ति बन जायें। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता, तो वह दुर्लभ सार्वजनिक साधनों को बरबाद कर रहा है।

और, विकासोन्मुख देशों के विश्वविद्यालयों द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषयों या डिग्रियों के सम्बन्ध में अन्य देशों की नकल करना उचित नहीं। अर्थशास्त्र का प्रोफेसर होने के नाते मैं नये देशों में पढ़ाये जाने वाले अर्थशास्त्र की बहुत-सी बातें पसन्द नहीं करता। यह अर्थशास्त्र इन देशों की समस्याओं की डाक्टरी ढंग से जाँच करने तथा उनके व्यावहारिक हल प्रदान करने की चिन्ता ही नहीं करता। उलटे वह बहुधा ही केम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लन्दन स्कूल या हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाजकल चालू, सर्वसाधारण के लिए अनुपयोगी तथा जटिल घादशों एवं पद्धतियों की नकल मात्र है। साधारण व्यक्ति की हैसियत

मे में कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या वास्तव में चिकित्सा-सम्बन्धी शिक्षा गरीब देश की स्थिति के अनुकूल अपनाई गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप में, और वस्तुतः नई दिल्ली में भी, हमें ऐसे डाक्टरों की अपेक्षा होती है, जो प्रशिक्षित तथा पूर्णतः विद्वत्सनीय हों। इस प्रकार का पूर्ण प्रशिक्षण आधुनिक चिकित्सा शिक्षा की अनिवार्य बात है। परन्तु विकासोन्मुख देश में, जिसके साधन अल्प होते हैं, यदि हम कुछ थोड़े से लोगों के लिए इन ऊँचे आदर्शों की ही बात करते रहें, तो क्या यह सम्भव नहीं है कि हम बहुसंख्यक समुदाय के लिए साधारण चिकित्सा सहायता भी न प्रदान कर सकें? क्या यह सच नहीं है कि राजधानियों में तो अच्छे से अच्छे डाक्टर मिल जाते हैं, और गाँवों में एक टूटी हुई ठीक करने वाला तथा साधारण चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाला भी डाक्टर नहीं होता?

घन विनियोग की समस्या हमेशा ही ऐसी पूँजी प्राप्त करना है, जो कम से कम मूल्य पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सर्वाधिक अनुकूल हो। चिकित्साशास्त्र तथा अर्थशास्त्र जैसे बिल्कुल ही भिन्न क्षेत्रों में इस बात का सकेत मिलता है कि पूँजी लगाने का ऐसा स्वरूप, जिसमें पैसा कम लगे तथा जो विकासोन्मुख देश की आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल हो, सचमुच खोजा जा सकता है। पारिभाषिक शब्दों में कहने पर इसका अर्थ यह हुआ कि घन विनियोग का अभिनवीकरण किया जा सकता है। अर्द्धविकसित देश के लिए बहुत आधुनिक ट्रैक्टरों की माँग महज इसलिए नहीं की जा सकती कि वे अमेरिका या रूस में प्रचलित हैं। यही बात शिक्षा के भी सम्बन्ध में लागू होती है।

पुराने विश्वविद्यालयों में, जैसाकि मेरा भी विश्वविद्यालय बहुत से शिक्षक प्रशिक्षण कार्य को अत्यन्त उच्च कार्य उसके प्रति एक दम्भपूर्ण धारणा रखने लगे हैं। हम का हमारा मुख्य कार्य अनुसन्धान करना या पुस्तकें आदि या बौद्धिक रूप से नेतृत्व करना है। हम यह मानते विश्वविद्यालयों को इससे ही पर्याप्त लाभ हो जाता है कि वे ह पर जाते हुए देख लें या सप्ताह में केवल तीन बार बेज लड़खड़ाती भाषा में बोले गये हमारे भाषण सुन लें। या की कसौटी उत्पादन-क्षमता है, तो इन दृष्टिकोणों के वि स्थान नहीं। फिर तो शिक्षक का कार्य अपने छात्रों को देना है, उनका इस प्रकार पथ-प्रदर्शन करना है तथा प्र प्रकार प्रोत्साहित करना है कि वे वास्तव में अधिक सम्पत्ति बन जायें। यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता, तो वह सार्वजनिक साधनों को बरबाद कर रहा है।

और, विकासोन्मुख देशों के विश्वविद्यालयों द्वारा जाने वाले विषयों या डिग्रियों के सम्बन्ध में अन्य नकल करना उचित नहीं। अर्थशास्त्र का प्रोफेसर होने में नये देशों में पढ़ाये जाने वाले अर्थशास्त्र को बहुत-पसन्द नहीं करता। यह अर्थशास्त्र इन देशों की समस्या से जाँच करने तथा उनके व्यावहारिक

वह बहुधा

बढ़ा

उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल है ।

सातपथ यह कि विकसितोन्मुख देश को अपनी शिक्षा-पद्धति का नियोजन विकासकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए । उसे पुराने तरीके की महज नकल नहीं करनी चाहिए । विकास-क्रम में वाद को माने के कारण नये देशों का यह सीमाग्र है कि वे अन्य लोगों के अनुभवों से सीख सकते हैं । परन्तु यह उनका दुर्भाग्य है कि अन्य देशों में जो बहुत कुछ विद्यमान है, उसकी नकल वे बिना हानि उठाये नहीं कर सकते । जैसा कि ऊपर मैंने संकेत किया है, नकल करने में भी अपने ढंग की उतनी ही परेशानियाँ हैं, जितनी नई पद्धतियाँ चालू करने में ।

, 7 ,

अब मैं इसी बात को संक्षेप में तथा एक आम नियम के रूप में कह देना चाहता हूँ। कोई विकासोन्मुख देश शिक्षा पर लगाये गये अपने पैसे, परिश्रम आदि को बिना किसी हिचक के धन विनियोग मान सकता है। इस बात से कि इनमें उपभोग के भी कुछ पहलू बिलम्बित होते हैं और वे अपने आप में ही व्यक्ति के लिए उचित पुरस्कार हैं, मुख्य प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं घाने देनी चाहिए। इस बात से कि कोई वस्तु उपभोक्ता सेवा तथा समाज के लिए उत्पादन-वृद्धि की साधन दोनों ही है, धन विनियोग के रूप में उसकी महत्ता रंचमात्र भी कम नहीं होती। उलटें इससे उसकी महत्ता बढ़ जाती है।

परन्तु जब हम शिक्षा को धन विनियोग मानें, तो हमें उसे सार्थक रूप में ही लगाने पर विचार करना चाहिए, जिस प्रकार हम अन्य किसी भी पूँजी व्यय के सम्बन्ध में सोचते हैं। पुराने तथा अपेक्षाकृत अधिक विकसित देश अनिवार्यतः ऐसा नहीं करते और न तो उनके लिए ऐसा करना आवश्यक ही है। उनकी परम्पराएँ भिन्न होती हैं; धन के प्राचुर्य ने उनके लिए अपेक्षाकृत निरुत्सर्गी होता सम्भव कर दिया है। नया देश उन लोगों के प्रति इतना ढीला नहीं हो सकता, जिनमें वह पैसा लगाता है। इन लोगों को समाज के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, तो इन्हें इन सुविधाओं का पात्र बनने के लिए परिश्रम करना चाहिए। शिक्षक लोग इस विशिष्ट राष्ट्रीय साधन के संरक्षक हैं और उन्हें इसे बरबाद नहीं होने देना चाहिए। देश को यह देखना चाहिए कि उसका शिक्षा-सम्बन्धी धन विनियोग

उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल है ।

मान्य यह कि विकासोन्मुख देशों की अपनी शिक्षा-पद्धति का नियोजन विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की ध्यान में रखकर ही करना चाहिए । उमे पुमाने तरीकों की महज नकल नहीं करनी चाहिए । विकास-क्रम में बाध की घाने के कारण नये देशों का यह भीभाय है कि वे धन्य लोगो के अनुभवो मे भीग सतते हैं । परन्तु यह उनका दुर्भाग्य है कि धन्य देशों में जो बहुत कुछ विद्यमान है, उसकी नकल वे बिना हानि उठाये नहीं कर सकते । जैसा कि ऊपर मैंने शकेत किया है, नकल करने में भी अपने ढंग की उतनी ही परेधानियाँ हैं, जितनी नई पद्धतियाँ चालू करने में ।



## 5

### उत्पादन का माध्यम

अब मैं विकासोन्मुख देश में औद्योगिक उत्पादन के माध्यम के सम्बन्ध में कुछ कहूँगा, विशेषकर उस सस्या के सम्बन्ध में, जो किसी भी स्तर पर आर्थिक क्रियाकलाप चालू रखने के लिए किसी न किसी रूप में अनिवार्य है। मेरा तात्पर्य निगम या कम्पनी से है।

पहले तो उत्पादन के निगमीय संघटन की अनिवार्यता पर बल दिया जाना चाहिए। भविष्य में आर्थिक व्यवस्था का क्या स्वरूप होगा, इस सम्बन्ध में संसार के सभी धर्म, आमतौर पर स्पष्ट एवं निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहते। बहुत दिनों से मेरे मन में बार-बार यह प्रश्न उठता है कि किसी अर्थशास्त्री ने अब तक फोर्ड फाउन्डेशन से इस सम्बन्ध में अनुसन्धान करने के लिए कोई अनुदान क्यों नहीं माँगा। जैसाकि ईसाइयों की धर्मगुरुओं द्वारा बतलाया जाता है, स्वर्ग में सोने का उपयोग सड़क पर पिटाई के लिए किया जाता है न कि मुद्रा बनाने के लिए। हमें यह भी बतलाया जाता है कि मुख्य उपभोक्ता सामग्री एक तार वाद्ययंत्र है। हम यह तो नहीं जानते कि इस अन्य सामानों के बनाने के लिए उत्पादन-मशीनरी ब

स्वरूप क्या है। परन्तु वहाँ के सम्बन्ध में भी इतना तो हम निश्चित रूप से कह ही सकते हैं कि यदि कुछ भारी पैमाने पर मालो का उत्पादन होता है, तो वह किसी औद्योगिक फर्म या निगम द्वारा ही होता होगा। हमारे इस भौतिक संसार में, किसी भी देश में, चाहे वह भारत हो या अमेरिका, या इंग्लैंड या रूस, जहाँ उत्पादन का कोई भी कार्य किया जायगा, फर्म का होना आवश्यक और अनिवार्य है।

इसका कारण सीधा है : आज के उत्पादन-सम्बन्धी उद्यमों में, जैसे इस्पात, अल्यूमीनियम, खाद, तारियों या मशीनों के औजारों आदि के बनाने में, हस्तकौशल एवं बौद्धिक प्रतिभा का विभिन्न रूपों में समन्वय करना पड़ता है, ताकि विभिन्न कार्य पूरे हो सकें। इस प्रकार के कौशल एवं प्रतिभाएँ दुर्लभ नहीं हैं, या यह भी नहीं है कि वे कुछ विशिष्ट लोगों या केवल किसी-किसी के पास ही हों। यदि उद्योग-धन्यों में औद्योगिक प्रतिभा का रहना अनिवार्य होता, तो मनुष्य की स्थिति बड़ी गम्भीर हो गई होती, क्योंकि औद्योगिक प्रतिभा तो विरले लोगों ही में होती है, और उसके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वह क्या और कहाँ और किस मात्रा में मिल सकती है। किसी औद्योगिक फर्म की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सर्वत्र उपलब्ध सामान्य प्रतिभा का समन्वय करके उससे ऐसे काम करवा लेती है, जो अकेले व्यक्ति नहीं कर सकते। वह एक गतिवृत्त व्यक्तिम्ब है, जिसमें बहुत से व्यक्ति संयुक्त हुए होते हैं और जिनका कुछ वह पूरा कर लेती है, उनका इन व्यक्तियों के अलग-अलग कार्यों का योग नहीं हो सकता।

यह संश्लिष्ट व्यक्तित्व सीधे-सादे छोटे पैमाने के उत्पादन, जैसे अधिकांश कृषि कार्य के लिए आवश्यक नहीं है। अधिकांश सरकारी कार्यों, जैसे न्यायिक कार्य, राजस्व की वसूली या सार्वजनिक शिक्षा के संचालन के लिए भी यह आवश्यक नहीं। ये कार्य तो कुछ व्यापक और स्थिर नियमों के अधीन पूरे किये जाते हैं। परन्तु प्राधुनिक उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता उसकी बड़े पैमाने की इकाइयाँ, जटिल शिल्प-विज्ञान तथा वे विभिन्न मार्ग हैं, जो भाज का बाजार उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। उसमें प्रत्येक आकस्मिक स्थिति के लिए पूर्वनिर्धारित नियम नहीं बने रह सकते। इसके बजाय उसमें निरन्तर बदलनेवाली परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदलते रहने की क्षमता चाहिए, और इस प्रकार का अनुकूलीकरण तभी सम्भव है, यदि बहुत से अलग-अलग व्यक्तियों के विभिन्न शिल्प-ज्ञान तथा अनुभव का आवश्यकता के अनुसार समन्वय हो सके। इस प्रकार का समन्वय निगम कर सकता है। और इन विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए वह एक दक्ष, बहुमुखी, भले ही सदिष्ट या वनावटी, व्यक्तित्व है।

यदि हम निगम को एक व्यक्तित्व के रूप में देखें, तो उसके प्रशासन के सम्बन्ध में हमें बहुत सी बातें समझ में आ जायें। सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वच्छन्दता की हावतों में ही अपना पूर्ण विकास कर पाता है। किसी एक व्यक्ति के आचार को बात-बात में किसी अन्य व्यक्ति के अधीक्षण में रखा देने से उसकी प्रतिभा घट जाती है और वह उतने अच्छे कार्य नहीं कर पाता। कोई व्यक्ति उस समय सर्वश्रेष्ठ कार्य

उमके समक्ष कुछ स्पष्ट लक्ष्य तथा साधन हों, जिनमें ज्ञान भी शामिल है, जिनके द्वारा स्वेच्छा में प्रेरित होकर वह इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। यही वात निगम के व्यक्तित्व पर भी लागू होती है। उत्पादन कार्य करनेवाले निगम के लिए भी स्वायत्तता, अर्थात् निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की स्वतन्त्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार स्पष्ट निर्धारित लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। ये बातें केवल महत्वपूर्ण ही नहीं हैं, ये तो मात्र एक ऐसी प्रशासकीय व्यवस्था हैं, जो किसी भी सफल निगम के लिए आवश्यक हैं।

## . 2 .

और स्पष्ट रूप में कहने पर इसका अर्थ यह हुआ कि इस संक्षिप्त व्यक्तित्व के समक्ष, जिसे हम फर्म या निगम कहते हैं, अपने विभिन्न अवयवों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने की पेचीदी समस्या रहती है। यह सहयोग तथा समन्वय बहुत अंश में तो स्वतः ही आ जाता है, निगम के कर्मचारियों के पारस्परिक मेल-मिलाप तथा विश्वास का यह परिणाम है। एक टेक्नोशियन किसी दूसरे टेक्नोशियन से सहायता लेकर अपने ज्ञान में वृद्धि करता है—वह जानता है कि वह किससे सहायता मांगे और यह भी कि जिस व्यक्ति से वह पूछता है, उसके ज्ञान तथा निर्णय पर वह कितना भरोसा कर सकता है। इसी प्रकार किसी शिल्प में कुशल श्रमिक भी किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा करता है, जब उसको दिया हुआ कार्य उसकी सामर्थ्य के परे हो जाता है। ऐसा वह स्वेच्छा से ही करता

है। व्यवस्थापक के लिए यह जानना आवश्यक है कि कब और किस प्रकार सहायता की जाय, परन्तु कोई एक व्यवस्थापक अकेले ही इस अर्थ में व्यवस्था नहीं करता कि सारे निर्णय वही करता हो। किसी सफल निगम में निर्णय करने का कार्य स्वयं निगम के ही अधिकार-क्षेत्र में निहित होता है।

इसी प्रकार, औद्योगिक फर्म में समय को लेकर ताल-मेर बैठाने के सम्बन्ध में अनेक तथ्या पेशीदा समस्याएँ हैं। प्राधुनिक औद्योगिक प्रक्रियाएँ एक-दूसरे पर बहुत ही आश्रित होती हैं। एक स्थान पर विलम्ब हो जाने पर सामान्यतया अन्यत्र भी उसी के अनुसार विलम्ब होगा। इसलिए समय से निर्णय करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से किसी परम्परागत सरकारी कार्यालय की तुलना में औद्योगिक प्रतिष्ठान की सर्वाधिक भिन्न एवं मुख्य बात यह है कि उसकी सफलता समय से निर्णय करने पर बहुत कुछ निर्भर करती है। किसी औद्योगिक फर्म में समय पर किया हुआ कोई बुरा भी निर्णय सामान्यतः इतना हानि-कारक सिद्ध नहीं होगा, जितना समय बीत जाने पर किया हुआ कोई अच्छा ही निर्णय। कोई बुरा निर्णय थोड़ी ही हानि उठाकर बहुत ही बढ़ता जा सकता है, परन्तु अच्छे निर्णय की प्रतीक्षा में जो समय गूँट हो जाना है, वह पुनः नहीं वापस ला सकता।

इसमें भीषण निष्कर्ष यह निकलता है कि निगम में स्वायत्तता का रहना गया उमे वाला दृष्टिकोण से सफलता का पराक्रम है। यदि साम्य दृष्टिकोण लोगों को प्रभावित करता है, तो वह उस बने-बनाये नापूर एव पेशीदा पारम्परिक मध्यमों को या तो खारिज कर देगा या पूर्णतः खोद कर देगा, जिस पर गहन महसूस का समय

प्राधारित होता है। उदाहरण के लिए, यदि बिना कुछ सोचे-गमभे किसी जाने हुए तथा योग्यतासिद्ध व्यक्ति को हटा लिया जाय और उसके स्थान पर अनजानी योग्यता या विश्वसनीयता का व्यक्ति रखा लिया जाय, तो तुरन्त ही यह अनिश्चितता उत्पन्न हो जानी है कि निर्णयों का उत्तरदायित्व किस-किस पर और कितना-कितना होगा या उस निर्णय की विश्वसनीयता सिद्ध हो जानी है, जिसमें नयागनुक व्यक्ति का भी हाथ होता है। अनिश्चितता तथा अनिर्णय उत्पन्न हो जाते हैं। बाह्य हस्तक्षेप का एक सामान्य रूप यह है कि कुछ प्रकार के निर्णयों की, जैसे साधन जुटाने में सम्बन्धित, उत्पादिन माल की डिजाइन से सम्बन्धित, उत्पादन दौली से सम्बन्धित, मूल्यों से सम्बन्धित आदि नियमों की पुनः जाँच की जाय। अनिवार्यतः इस जाँच में समय लगता है। इसके परिणामस्वरूप समय से सम्बन्धित समन्वय कार्य में बाधा पड़ती है। घुरे निर्णय रोकने के प्रयास में विलम्बित और फलतः महँगे निर्णय करने पड़ते हैं।

मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि निगम के व्यक्तित्व पर अच्छे इरादे से किए गये तथा घुरे इरादे से किये गये दोनों प्रकार के हस्तक्षेप का घुरा प्रभाव पड़ता है। दोनों में से कोई भी उपयुक्त नहीं।

### . 3 .

आधुनिक अमेरिकी संघटन तथा आधुनिक सोवियत संघटन दोनों ही में स्वशासन के लिए निगम की आवश्यकताओं पर बड़ा ध्यान दिया गया है। कोई आधुनिक अमेरिकी विशाल

निगम अपने शेयरहोल्डरों से, जो वाह्य हस्तक्षेप के प्रधान जरिये है, पूर्णतया स्वतन्त्र रहता है। यद्यपि दिखावे के लिए यही माना जाता है कि शेयरहोल्डरों का ही लोकतन्त्रीय नियन्त्रण है, व्यवहार में मान्यता इसी बात को दी जाती है कि शेयरहोल्डरों द्वारा व्यवस्था में अधिक हस्तक्षेप अत्यन्त हानिकारक होगा। (अमेरिका की एक बड़ी विमान सेवा कम्पनी के मुख्य शेयरहोल्डर के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है, जिसमें यह माँग की गई है कि वह अपनी कम्पनी की व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे।) इन प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ तक उत्पादन सम्बन्धी निर्णयों का प्रश्न है, सभी वास्तविक अधिकार निगम में ही होता है। सरकार से भी इस अधिकार की रक्षा बड़ी सतर्कता से की जाती है।

मैं रूसी ढंग की अर्थ-व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में इतने विश्वास के साथ नहीं कह सकता। परन्तु इतना तो निश्चय है कि हाल के कुछ वर्षों में किसी भी बात पर इतना बल नहीं दिया गया है, जितना व्यवस्थापकों को वह स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता दिये जाने की आवश्यकता पर, जिसके बल पर वे अपना कार्य कर पाते हैं। रूसी कारखानों के व्यवस्थापक, जो अपने कार्य में बहुत दक्ष होते हैं और जिन्हें देखकर कोई भी विदेशी पर्यटक प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, सफलता से अपने उत्तरदायित्व निर्माण के लिए इस प्रकार की स्वायत्तता पर बार-बार बल देने रहते हैं।

परन्तु किसी विकासोन्मुख देश में, निगम की स्वायत्तता के सम्बन्ध में एक विशेष बाधा उपस्थित हो जाती है। इसका एक कारण तो यह है कि निगम ने इस प्रकार के संशोधन करने की मर्त्ता को इम्नांकित नहीं है। परन्तु मुख्य कारण तो यह है कि

एच तथा परिस्थितियों के अनुसार यह आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार के देशों में अधिकांश कम्पनियाँ सरकार के निर्देश में ही संचालित हो और लोकतांत्रिक देशों में समदीय प्राधिकार के अधीन रहकर संचालित हो ।

## 4

किसी समदीय प्रकार के लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर जनता का स्वामित्व एक विशेष प्रयोजन में होता है । एक स्पष्ट प्रयोजन तो यह है कि उद्योग पर काफी हद तक लोकतांत्रिक नियंत्रण रहे । इस नियंत्रण से यह तो निश्चित हो जाता है कि फर्म की कार्यविधियाँ एवं निर्णय जनता के हित में होंगे, अर्थात् उनके निर्णय विश्वमनीय तथा तर्कमग्न होंगे और आम जनता की भलाई के लिए ही होंगे । यदि इस नियंत्रण को लागू करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, तो चाहे कुछ भी हो, कुछ लोग तो यह कहेंगे ही कि सार्वजनिक स्वामित्व निरर्थक है । यद्यपि यह बड़ा तर्कमग्न एवं निर्दोष जान पड़ता है, विशेषकर उम मूल में, जब हम विवाद में 'लोकतांत्रिक नियंत्रण' वाले जादू-भरे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, इस निष्कर्ष में एक गम्भीर प्रतिवाद है, जिसे हम बहुधा देखते भी नहीं । यदि निगम में काम करने वाले व्यक्ति निगम में बाहर की किसी शक्ति के नौकर हैं, फिर वे मण्डन के लक्ष्यों की बिना अपने ध्यान नहीं करेंगे । उम मूल में, चाहे कुछ भी कहिये, उनका दायित्व दोतरफा हो जाता है । एक दायित्व तो निगम के प्रति रहता है और दूसरा — श्रमिक के प्रति । एक साथ मण्डन पर रहती है और





हो गके । चिन्मय मे किये गए निर्णयो की आनोनना भले ही  
वर ली जाय, उन्हें आशानी मे मुधाग नही जा सगता । और  
गनन निर्णयो मे भी वचना आयदयक है, भले ही समय से न किये  
जाने याने निर्णय मूनत अपेक्षाकृत अधिक हानिप्रद हो ।

मैं यह दुहरा देना चाहता हूँ कि गमस्या यह नही है कि  
हस्तक्षेप अच्छे उद्देश्य मे या बुरे उद्देश्य से किया जाता है ।  
गमस्या का सम्बन्ध तो उम बात मे है, जो फर्म या निगम मे  
हस्तक्षेप करती है, उसे तोडती-भरोटती है या उसे बरवाद करती  
है । यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि बाह्य हस्त-  
क्षेप स्वायत्तता को नष्ट करने के बाद बुद्धिमानी या अपने सच्चे  
उद्देश्य की भाड मे हमेशा ही अपने कार्य का अधिन्य सिद्ध  
करना चाहेगा । यह भी कोई तर्क है ?

## 5

मैं ऊपर कह चुका हूँ कि कोई भी कम्पनी या फर्म, व्यक्ति  
की भांति, तभी दक्षता से कार्य कर सकती है, यदि उसे कुछ  
निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की स्वतन्त्रता  
हो । ऐसा होने से उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो पाता है ।  
किसी समदीय लोकतंत्र मे सार्वजनिक नियम की दूसरी बड़ी  
समस्या उसके लक्ष्यों को लेकर है । बड़ी विचित्र बात है कि  
उपर तो यह भी सतरा है कि समदीय या अन्य कोई सार्वजनिक  
प्राधिकार निर्णय करने के कार्य मे हस्तक्षेप करके फर्म को नुक-  
सान पहुँचाने का परित्यज्य न दे । निश्चित लक्ष्यों के अभाव  
में सं



बिताना कि उन्होंने अच्छा कार्य किया है, बहुधा ही अपने लिये श्रेयस्कर समझते हैं, न कि अच्छा काम करने के प्रयत्न में।

४

मैं इसका हल क्या समझता हूँ, इसके सम्बन्ध में मैं पाठकों के मन में कोई सन्देह नहीं रहने देना चाहता। औद्योगिक फर्म, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, औद्योगिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। उनकी कई मांगें होती हैं, मुख्य मांग तो यह है कि दिन-प्रतिदिन के निर्णय करने के कार्य में उसे स्वतन्त्रता हो, लगभग पूर्ण स्वतन्त्रता। यह स्वतन्त्रता गलती करने के अधिकार में भी हो, क्योंकि गलती बहुधा ही तेज गति से काम करने के मूल्य के रूप में ही होगी, और वह भी बहुत छोटा मूल्य। सैनिक कार्यों के संचालन में भी स्वतन्त्रता उतनी ही आवश्यक है। वह भी स्वाभाविक तौर पर प्रदान की ही जाती है। और इसी प्रकार नहीं किया जा सकता कि सेनापतियों ने गलती करने के अपने अधिकार का पूर्णतः प्रयोग किया है। सैनिक ज्ञान में ऐसा विलम्ब, जो गलती बचाने के लिए किया जाना चाहिए एक घातक अवरोध माना जाता है। अमेरिका में वर्ष पहले हमारी एक बड़ी मोटर कम्पनी ने एक ऐसी मोटर की जिसमें एक भारी त्रुटि रह गई थी। यह कम्पन कर लक्ष्य किया गया कि जनता एक ऐसी बड़ी मोटर चाहती देखने में ऐसी सगे जैसे किसी अत्यन्त बलित मोटर की। बहुत जनता का हमने खेवना भी अनुभव की था।

अब शायद जितने स्वतन्त्रता का निम्न होना, तो दर्श

में सावर्जनिक स्वामित्व वाली फर्म की सफलता का मापदण्ड बहुत स्पष्ट नहीं होगा।

अमेरिका या पश्चिमी यूरोप के किसी आधुनिक औद्योगिक निगम के लक्ष्य काफी हद तक निश्चित होते हैं : मोटे तौर पर सर्वाधिक सफल निगम वह होता है, जो लाभ भी काफी करता है और जिसकी विकास-गति अपने प्रतिद्वन्द्वियों की अपेक्षा तीव्र होती है। (किसी उन्नतिशील निगम का प्रधान होना अमेरिका में निस्सन्देह एक गर्व एवं आत्मश्लाघा की बात है, परन्तु उस सामान्यतया बड़ी फर्म को अनिवार्यतः अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है, जिसके विस्तार की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है।) उत्पादन तथा लाभ के लिए लक्ष्य निर्धारित करना एवं इन लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उनसे भी आगे बढ़ जाने के लिए प्रयत्न करना, सोवियत नियोजन की एक मार्क की बात है।

विकासोन्मुख देशों में सावर्जनिक निगम के लक्ष्य कदाचित् ही कभी इतने स्पष्ट होते हों। लाभ को अधिराधित बढ़ाना सन्देहात्मक रूप में पुराने ढंग का पूंजीवाद समझा जाता है, जिसे बहुत से नये देश अस्वीकार कर देते हैं। आगे बढ़ने तथा विस्तार करने की इच्छा कदाचित् ही कभी निश्चित एवं दृढ़ होती हो। आदर्श प्रकार के ही लक्ष्य, जैसे ग्राम जनता की सहायता सेवा करना या श्रमिकों की विन्या करना ग्राम रूप में निर्धारित होते हैं। उनका आदर्श प्रकार का होना ही उनके माप में बाधक होता है—कोई भी उनके मध्यम में यह प्रश्न उद्भिन्न कर सकता है कि इन आदर्शों की पूर्ति हो रही है या नहीं। या इनके लिए उत्तरदायी होने हैं, वे इन्हीं चीज होने में समर्थ।

है। इसी प्रकार उसमें धर्मनिरपेक्ष सेवा की कार्यविधियों एवं नित्य नियमों का प्रवेश भी हानिकारक है। इन कार्यविधियों एवं नियमों का प्रयोग करने ही इस स्तुत्य उद्देश्य से किया जाय कि सभी कर्मचारियों के प्रति समानता का व्यवहार हो, परन्तु इसका परिणाम यह हो सकता है कि व्यक्तियों के वैचारिक मीचे-मादे समाधान तथा आत्मप्रेरित समन्वय एवं सहयोग नष्ट हो जायें, जिन पर कार्य का सफल संचालन आधारित होता है।

संसार में बहुत सी बातों में वाञ्छनीय के ऊपर अवाञ्छनीय की बरीयता देकर उसे स्वीकार करना पड़ता है, और आधुनिक उद्योगवाद में ऐसी ही एक बात पूर्णतः न्यायसंगत नियमों तथा काफी हद तक सन्तोषप्रद सफलता के बीच बरीयता देने की है।

## . 7

परन्तु यदि निगम को उसके निर्णयों के सम्बन्ध में वाह्य प्राधिकार के हस्तक्षेप से बचाना श्रेयस्कर है, तो साथ ही वाह्य अधिकार को भी निगम को आदेश देने में कोई नरमी नहीं चाहिए। उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य बहुत स्पष्ट तथा सीधी-सादी भाषा में व्यक्त होने चाहिए। यह ठीक है कि सभी राज्यों में सफलता को ही उसका सबसे बड़ा पुरस्कार समझा है, परन्तु इसके सम्बन्ध में कभी कोई सन्देह नहीं रहना है कि सफलता किसे कहते हैं।

दि मुझे किसी विकासोन्मुख देश के सार्वजनिक निगमों के सम्बन्ध में कोई मापदण्ड निर्धारित करना हो, तो

कटु आलोचना हुई होती। इसके बाद निश्चित रूप से यह आवश्यक कर दिया जाता कि अब आगे से कार के डिजाइन में किये जाने वाले सभी वांछित परिवर्तन सार्वजनिक परीक्षाओं के एक बोर्ड के समक्ष रखे जायें। ऐसा करने से सम्भवतः भविष्य में फिर ऐसी गलती न हुई होती। परन्तु यह भी तो सम्भव था कि जब तक बोर्ड मोटर की सुन्दरता की समस्याएँ हल कर पाता, तब तक यहाँ कार्य में बहुत विलम्ब होता, जो अन्त में बड़ा मंहगा पड़ता। इस प्रकार की कार्य-स्वतन्त्रता की आवश्यकता केवल हमारी ही पद्धति या अन्य किसी एक पद्धति के लिए ही नहीं है। निगम का स्वरूप ही ऐसा होता है कि यह स्वतन्त्रता सभी पद्धतियों के लिए आवश्यक है।

इस स्वतन्त्रता में कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा उन्हें बरखास्त करने की भी स्वतन्त्रता रहनी चाहिए। परन्तु इन विचार से कि इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग न हो, ऐसा एक निश्चित मान के अनुसार ही किया जाना चाहिये। विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को, विभिन्न शर्तों पर, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्त करने की स्वतन्त्रता रहने पर ही एक व्यक्ति का कौशल किसी दूसरे का, तथा किसी एक व्यक्ति का ज्ञान अन्य व्यक्ति के ज्ञान का पूरक हो सकता है, तथा यह स्वतन्त्रता ही कर्म नामक संक्षिप्त व्यक्तित्व को इतना समर्थ बना देती है कि जो कुछ वह कर सकता है, कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मानव-जनिक निगम में राजनीति एवं बाह्य सम्बन्धों के प्रवेश उन मान-रिब, पेशावा एवं नाबुक सम्बन्धों के लिए बहुत हानिकारक है, जिन पर *the* *business* का स्वयं विभाग निर्भर है।





में इसे उमके द्वारा उम अर्जित धन को ही मानूंगा, जो वह अपने विस्तार के लिए प्रदान करता है। किसी निदिष्ट या तत्सम्बन्धित क्षेत्र में, योजना के ढाँचे के अन्दर ही रहकर, इस प्रकार का विस्तार सार्वजनिक क्षेत्र की किसी भी फर्म का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मर्यादित सफल फर्म वह कही जायगी, जो अपनी दक्षता तथा प्रयत्नों से इतना धन अर्जित कर लेती है कि उसका अधिकतम विकास हो सके। कदाचित् अन्य और भी लक्ष्य वाछनीय हो। परन्तु आवश्यक यह है कि लक्ष्य चाहे जो भी हो, वह निश्चित हो, उसकी सफलता या असफलता माँकी जा सके, वह सर्वविधि हो तथा दृढ़ता से वह कार्यान्वित की जाय।

यद्यपि समाज को उन गलतियों को क्षमा कर देना चाहिये, जो सफलता की प्राप्ति के प्रयत्न में हो जायें, उसे उस असफलता को कभी नहीं सहन करना चाहिये जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में हो। सच तो यह है कि लक्ष्यों का न प्राप्त कर सकना ही असफलता है, न कि कोई एक विशिष्ट गलती। स्वायत्तता का अर्थ यह नहीं कि जनता के समक्ष आप कम उत्तरदायी हैं। उल्टे, आप अधिक उत्तरदायी हैं। परन्तु यह उत्तरदायित्व तरीके, कार्यविधि या व्यवितगत कार्य को लेकर नहीं है, अपितु परिणाम को लेकर है।





